(Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2020-21)' of Ministry of Housing and Urban Affairs.

STATEMENT REGARDING ORDINANCE

The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Hon. Chairman, Sir, I lay on the Table, a statement (in English and Hindi) explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021.

GOVERNMENT BILL

The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Hon. Chairman, Sir, I move for leave to introduce a Bill to amend the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI G. KISHAN REDDY: Sir, I introduce the Bill.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS*

MR. CHAIRMAN: To continue with the discussion on Motion of Thanks on President's Address...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, one minute. In view of the fact that the Central Hall is able to accommodate 240 Members, I would request you to review the seating arrangement in the Rajya Sabha to accommodate more Members in the House, so that there is an atmosphere of debate.

---

* Further discussion continued from the 3rd February, 2021.

MR. CHAIRMAN: We will discuss it because to my knowledge, the original arrangement for Central Hall is 244. But, after I reviewed, I sent a word to the Speaker saying that we would then not be following social distance. So, that has been reduced to 100 and odd. I don't exactly remember. But, you meet me; we will discuss, no problem.

Now, we will continue with the discussion. Prof. Manoj Kumar Jha. आप बैठ कर भी बोल सकते हैं, खड़े होकर भी बोल सकते हैं, जैसा आप चाहें।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सर, मैं पीठ के सामने खड़ा होना चाहूँगा।

श्री सभापति : ठीक है, खड़े हो जाइए।

प्रो. मनोज कुमार झा: सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, दिक्कत यह है कि:

उनसे, जिनसे होती है इंसां को हमेशा तकलीफ,
वे समझते हैं कि वे असल अक्ल वाले हैं।

महोदय, पंचतंत्र में एक कहानी है, जिसमें चित्ररथ नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके पास एक विशाल सरोवर था और उस सरोवर में बहुत सारे छोटे-छोटे खूबसूरत हंस थे। वे 6 महीने में एक पंख गिराते थे और पंख राजा को दे देते थे। बीच में सोने के तथाकथित पंख वाला एक बहुत बड़ा पक्षी आया और उसने कहा कि मैं इस सरोवर में रहूँगा। छोटे पक्षियों ने कहा कि महाराज, हम 6 महीने में राजा को पंख देते हैं, इसलिए आपके लिए यहाँ गुंजाइश नहीं है। वह सोने के तथाकथित पंख वाला पक्षी राजा के पास पहुँच गया। उसके सिपहसालारों को कहा कि देखो, ये तो तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं और सरोवर पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। राजा ने अपने सिपाही भिजवा दिए। उसने सारे हंस मार दिए और वह जो सोने के तथाकथित पंख वाला बड़ा विशाल पक्षी था, वह भी उड़ गया। मैं इसका संदर्भ अपनी सरकार पर, सत्ता प्रतिष्ठान पर छोड़ता हूँ।

एक माननीय सदस्य : जमा नहीं।

प्रो. मनोज कुमार झा : अभी जमेगा, इंतज़ार करिए।

श्री सभापति : प्लीज़।

प्रो. मनोज कुमार झा : हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं कि दूध में जोड़न ढंग से पड़े तो दही बढ़िया जमता है। अभी जोड़न डाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने इस कथन को चन्द खंडों में रखूँगा। पहला खंड होगा कि महामहिम के अभिभाषण का संदर्भ, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। दूसरा, लोकतंत्र में आंदोलन की क्या भूमिका होती है। तीसरा, पीसफुल असेंबली के साथ कोई भी लोकतांत्रिक मुल्क कैसे डील करे। चौथा, आंदोलनों और लॉ मेकिंग के बीच में क्या ताल्लुक है और पाँचवाँ, repression की कहाँ इंतहा होती है। लोकतंत्र के तीन स्तंभों के बारे में हम सब जानते हैं, चौथे स्तंभ के बारे में तो मैं बोलूँगा भी नहीं। अगर आपके वैसे दोस्त हों -- जिस चौथे स्तंभ पर, एक बड़ी धारा पर आप निर्भर हैं, आपको दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, वे दोस्त ही आपका काम तमाम कर देंगे। वे क्या करते हैं? दिन भर कुछ भी मामला हो, लोग दुख में हों, लोग संकट में हों, लोगों की मौत हो रही हो, लेकिन शाम को चलाएंगे - Khalistani angle of *Kisan Andolan*. सर, मैं कॉलेज का विद्यार्थी था। हमने देखा है कि पंजाब और पूरे मुल्क ने क्या भुगता है, यह हम सबने देखा है। आप तो सक्रिय राजनीति में थे। सक्रिय राजनीति में आपने देखा कि पूरे देश ने क्या भुगता। हमने सिर्फ प्रधान मंत्री ही नहीं खोया, हमने हज़ारों-लाखों जानें गवाईं। कुछ तो सीखें इतिहास से! इतिहास दोहराता नहीं है, लेकिन इतिहास प्रेरणा देता है, इतिहास निर्देश देता है, लेकिन हम उन निर्देशों को सुनना नहीं चाहते। शाम ढलते ही चलाया जाता है कि खालिस्तानी जमा हो गए, पाकिस्तानी जमा हो गए, टुकड़े-टुकड़े गैंग जमा हो गए, नक्सली जमा हो गए, माओवादी जमा हो गए। सर, सबसे बड़ा टुकड़े-टुकड़े गैंग वह है, जो अपनी भारत माता की संतान की पीड़ा को करुणा से न समझे, बल्कि दंभ से देखे, गुरूर से देखे। दंभ और गुरूर लोकतंत्र की ज़ुबान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बहुत लोग तो नहीं, लेकिन इनके कुछ मंत्रीगण 303 आंकड़े के बारे में कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस सदन ने इतिहास में इससे बड़े आंकड़े देखे हैं, कहाँ बिला गए, कहाँ गुम हो गए, किसी को पता नहीं है। आंकड़े इतिहास नहीं तय करते हैं, आंकड़ों के पीछे की संजीदगी और संवेदना इतिहास तय करती है । आपका हाई प्वाइंट क्या है, आपका लो प्वाइंट क्या है, आप उसमें फेल हो रहे हैं। मैं lighter vein में कहना चाहता हूँ कि 303, थ्री नॉट थ्री नाम की एक रायफल हुआ करती थी, उसकी सर्विस समाप्त हो गई है।**...(व्यवधान)...** उसकी सर्विस समाप्त हो गई है। सर, मैं एक बात और कहकर मूल बिंदु पर आऊंगा। हम Macbeth से बहुत बातें सीखते हैं। शेक्सपियर ने अदभुत चीज़ लिख दी है। सत्ता प्रतिष्ठान में temperance बहुत ज़रूरी है। कद तब बढ़ता है, जब आप पद की गरिमा समझते हैं। " Boundless intemperance In nature is a tyranny. It hath been The untimely emptying of the happy throne And fall of many kings." अगर आपके स्वभाव में intemperance आ जाए, तो इसने कितने ही सिंहासन खाली करवा दिए, कितने ही राजाओं की घर वापसी करवा दी, यह थोड़ा सनद रहे, थोड़ा ध्यान रहे।**...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Please, please. That is not acceptable.

प्रो. मनोज कुमार झा : माननीय सभापति महोदय, मैं हल्के स्वर में एक बात कहना चाहता हूँ। जयराम रमेश जी सेंट्रल हॉल का ज़िक्र कर रहे थे। मैं जब वहाँ बैठता हूँ, तो लोग दल से ऊपर सोचते हैं। हमारे भाजपा के कई मित्रों ने पूछा कि इस आंदोलन का स्वरूप क्या है, कैसे खत्म होगा? दिक्कत यह है कि आप सेंट्रल हॉल में तो पूछ लेते हैं, लेकिन सदन में ज़ुबान नहीं खोलना

चाहते हैं। जब यह बिल आया था, तब मैंने कहा था कि दलों के दायरे और उस व्हिप से ऊपर निकलकर देखिए, क्योंकि किसान देख रहा है, उसने व्हिप जारी कर दिया है और अगर आप उसके व्हिप को नहीं सुन रहे हैं, तो पता नहीं -- लोकतंत्र में तो हम सुनते थे कि सुनना और सुनाना, दोनों लोकतंत्र की अदभुत कला होनी चाहिए। आप सुनाने में यकीन करने लगे हैं, सुनना भूल गए हैं, खासकर इस टर्म में तो बिल्कुल ही भूल गए हैं।। Anyway, Sir.

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है। हम सब जानते हैं कि सरकार स्क्रिप्ट तैयार करती है। बीते 29 जनवरी को जब महामहिम का अभिभाषण हुआ था, उसमें हममें से 19 दलों ने शिरकत नहीं की थी, यह मैं माफी के साथ कहता हूँ। हमें कष्ट भी हुआ था, क्योंकि वह एक बहुत महत्वपूर्ण occasion होता है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण समकालीन यथार्थ से, दुख और दर्द से, रंज-ओ-ग़म से मीलों दूर खड़ा हो, तो कैसे शामिल हो जाएं? बड़ी मुश्किल होती है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर, ये छोटे-छोटे हलकों में तीन महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। अभी बिहार में नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी जी और कम्युनिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने मिलकर मानव-श्रृंखला बनाई। तो पूरे देश में कहीं न कहीं churning हो रही है और इस churning के पीछे का साक्ष्य क्या है? **...(व्यवधान)...** माननीय सभापति महोदय, मैं एक आग्रह करूँगा। मैंने सदन में आज तक कभी भी किसी पर टीका-टिप्पणी नहीं की है, तो सदन की बहस में टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बस, इतना आग्रह है। सर, हमने तो वह इतिहास भी देखा है कि एक पार्टी, जो दो सीट पर सिमट गई थी, वह आज कहाँ पहुँच गई, इसलिए इस चक्कर में न पड़ा जाए।

सर, महामहिम के अभिभाषण को पढ़ने के बाद पहला ख्याल आया कि कही पर कहूँ या अनकही पर बोलूँ। जो कही गई बात है, उसके बारे में अब मैं यह पहली चीज़ कहता हूँ। "My Government holds in high esteem the values of democracy and sanctity of the Constitution." अगर मेरी memory सही serve करती है, तो यह संभवतः पेज 7 का पैरा 25 होना चाहिए। Yes, Para 25. सर, अब इसको व्यापक संदर्भ में देखना होगा कि "My Government holds in high esteem the values of democracy and sanctity of the Constitution." हमने हाल के दिनों में जो भी देखा है, वह संविधान से इतर देखा है। सर, value of democracy सिर्फ एक rhetorical value नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको quote करना चाहता था। मैंने उसे आगे रखा था, लेकिन वह अभी मेरे ज़हन में आ गया। Recently you have said, "nationalism and patriotism is not simply sloganeering 'भारत माता की जय', 'जय हिन्द' or 'जन-गण-मन' ". No, Sir. The greatest act of patriotism is to speak about the well-being of the nation, and that does not mean that I should stand in the orchestra party of the Government forever and always. You have never done it when you were in the Opposition and we shall not do it when we are in the Opposition. We would support you. हम समालोचना करेंगे, लेकिन आप यह उम्मीद नहीं करेंगे कि आपके खिलाफ का हर एक

शब्द, हर एक लफ्ज़ देशद्रोही है! मैंने सदन में पहले भी कहा था कि एक मशीन बनावाइए। कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई है, अब एक मशीन बनवाइए कि किसके अंदर देशभक्ति का पारा कितना है। सर, हो सकता है, आपको झटका लग जाए। देशभक्ति sleeve पर नहीं चलती है, यहाँ दिल में रहती है, उसका सीने से कम ताल्लुक है।

सर, एक और interesting चीज़ यह है कि अभी बंगाल में चुनाव हैं, तो पेज नम्बर 26 के पैरा 91 में गुरुदेव के बड़े भाई, ज्योतिरीन्द्रनाथ टैगोर जी का ज़िक्र हुआ, "चॉल रे चॉल शॉबे, भारोत शन्तान।" बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके बाद गुरुदेव की अपनी लाइन where the mind is without fear and the head is held high जोड़ दीजिए। कहाँ है? दोनों को जोड़कर देखिए। डेमोक्रेसी में cherry-picking नहीं चलती है। आप cherry-picking के उस्ताद हो गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, आंदोलन लोकतंत्र की जीवंतता का उदाहरण होता है। ज़िन्दा लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र आंदोलन के साथ सदैव, निरंतर सम्वाद की कोशिश करता है। सर, मैं यहाँ एक आशय रखना चाहता हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जिस विभाग में पढ़ाता हूँ, वहाँ मेरा एक विषय मूवमेंट भी है। सर, मैंने बहुत सालों से आंदोलन पढ़ाया है। आंदोलन की तीन महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं- alienation, attraction, conversion. यानी कि अलगाव की चीज़ कहीं आई, उसके बाद आपका किसी विचारधारा से आकर्षण हुआ, उसके बाद आप सड़कों पर आए। सर, हमने आंदोलनों को न जाने किस नज़रिये से देखना शुरू किया है? माननीय सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा- वह सरिया, वह कील, वह खाई! सर, मैं सरहद पर कभी गया नहीं हूँ, लेकिन सरहद की जो तस्वीरें देखी हैं, वे भी ऐसी नहीं देखी हैं। आप किससे लड़ रहे हैं? आप अपने किसानों से लड़ रहे हैं और वे क्या कह रहे हैं? वे आपसे चाँद नहीं माँग रहे हैं, वे अपना हकूक माँग रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, हममें से किसी को यह मुग़ालता न रहे कि किसान और खेतिहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। नहीं, वे अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं। आप उनको समझाने चले हैं कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है! क्यों समझाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों 'खालिस्तान','पाकिस्तान','टुकड़े-टुकड़े' angle लाने की ज़रूरत पड़ रही है? हमारा लोकतंत्र बहुत मज़बूत है, किसी के एक ट्वीट से कमज़ोर नहीं होगा। आपने विमर्श को कमज़ोर कर दिया है। हमारा लोकतंत्र बहुत मज़बूत है। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि अगर आपके दौर में जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ होता-- इस सदन में अभी कई लोग हैं, जो जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए हैं, including सभापति महोदय। आप जेपी के आंदोलन की कल्पना कीजिए। अगर जेपी को इन खाई, बाड़ों, कंटीले तारों आदि को देखना पड़ता तो क्या होता? हमारे कई मित्र बिहार से भी हैं, जो जेपी आंदोलन से निकले हैं। एक बार दलीय दायरों को छोड़कर सोचें कि आंदोलन को डील करने का क्या यह नज़रिया उचित है? आप कहेंगे 'नहीं'।

महोदय, मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं-- आप कहते हैं कि 11 दौर की बातचीत हुई है, दिक्कत यह है कि किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान में एकालाप और वार्तालाप का फ़र्क समझना चाहिए। There is a difference between monologue and dialogue. आपके साथ दिक्कत है

कि आप monologue को dialogue का कपड़ा पहनाते हैं। मैंने माननीय मंत्री महोदय को सुना जो वार्ता में थे, उन्होंने कहा कि हमने यह दिया, वह दिया। महोदय, लोकतंत्र में खैरात की ज़ुबान नहीं होती है। आप देने वाले कौन होते हैं? हम देने वाले कौन होते हैं? वे दे रहे हैं, उन्होंने ही आपको 303 का आंकड़ा दिया। और आगे के तीन और शून्य कब उड़ जायें, यह भी वही तय कर देंगे, इसलिए यह ज़ुबान बंद कीजिए, एकालाप और वार्तालाप के बीच की दूरी को खत्म कीजिए।

महोदय, मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं कि देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं है। देश सिर्फ सेना, पुलिस के जवान, जन-गण-मन और वंदे मातरम् नहीं है। देश रिश्तों से बनता है और आपने रिश्तों को रिसा दिया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि मुल्क रिश्तों से बनता है- आपने कितने रिश्ते खत्म कर दिए? सरकारें पुल बनाने के लिए लायी जाती हैं, चाहे वे नदियों पर पुल हों या रिश्तों का पुल हो। आपने तो पुल के बदले कंटीली दीवारें खड़ी कर दीं। महोदय, सीएए का आंदोलन हुआ, जिसमें नागरिक को नागरिक के खिलाफ खड़ा कर दिया, आप तो कमाल हैं! मैं तो आपके समाजशास्त्र के ज्ञान से भी चकित हूं कि जिस दिल्ली पुलिस के जवान को आप किसान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, आप उस दिल्ली पुलिस का सोशल प्रोफाइल देख लीजिए। जिन इलाकों में यह आंदोलन ज्यादा प्रबल है, उन इलाकों का एक बच्चा सरहद पर रहता है, एक बच्चा पुलिस में रहता है और एक बच्चा खेत में रहता है। वे बच्चे जायदाद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपने उन्हें भी भिड़ा दिया। आप कहीं तो सोचिए, विराम दीजिए। इसलिए मैं अवतार सिंह पाश की एक कविता को कहता हूं:-

"यदि देश की सुरक्षा यही होती है
कि बिना ज़मीर होना जिन्दगी के लिए शर्त बन जाए,
आंख की पुतली में हां के सिवा कोई शब्द न हो।"

आपको आंख की पुतली में सिर्फ 'हां' चाहिए, चाहे वह कितना भी अश्लील हो। यह पाश कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं।

"और मन बदकार पलों के समझ हमेशा झुका रहे,
तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है।"

देश को अपनी सुरक्षा से खतरा नहीं है, यह फर्क आपको समझना होगा। महोदय, कितना समय बचा है?

श्री सभापति : आपका allotted time 18 मिनट है। आपने ऑलरेडी 17 मिनट ले लिए हैं।

प्रो. मनोज कुमार झा : महोदय, आप मुझे सिर्फ दो मिनट दे दीजिए।

श्री सभापति : ठीक है, आप दो मिनट ले लीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा : माननीय सभापति महोदय, मै दो मिनट का समय लूंगा। आपने किसान को लेकर जितनी बातें कहीं, उन बिलों के बारे में मैं पिछले सत्र में बोल चुका हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिहार में एमएसपी वर्ष 2006 में खत्म किया गया। बिहार के किसान की आय के बारे में मैं आपको आंकड़ा दूं तो यह उचित नहीं होगा। आपके पास आंकड़ों का भण्डार है, आप आंकड़े तैयार कर लेते हैं, बल्कि कभी-कभी प्रेशर कुकर में पका भी लेते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप बिहार के मॉडल को-- मैं सिर्फ आपकी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, बीती कई सरकारों ने बिहार को लेबर सप्लाई का स्टेट बनाकर रख दिया है। हमारा काम पूरे देश में मज़दूर भेजना है। हमने कोरोना के काल में वह सब देखा है। हम तो सोच रहे थे कि हमारे बिहार का किसान-- हालांकि वह किसान नहीं रहा, बल्कि खेतिहर मज़दूर हो गया है-- हम सोच रहे थे कि उसे भी पंजाब और हरियाणा की तरह बनाया जाए। आप वह मॉडल चाह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में बिहार की तरह हालात हो जाएं। मुझे कभी-कभी इस बात का अंदेशा होता है कि संसद का भी वर्ग-चरित्र बदल गया है। अभी संसद में अगर किसान और किसानी समाज से आने वाले लोग होते, तो आप इतनी आसानी से bulldoze नहीं कर पाते। मेरे स्वयं के नेता लालू प्रसाद जी के सामने कई ऐसे मसले आए, उन्होंने यह तय किया--और आपके लोग भी थे, आप उन्हें भूल चुके हैं, जिन्होंने खड़े होकर यह कहा कि हम यह नहीं होने देंगे।

सर, अभी भी आपकी रीढ़ किसान और किसानी ही है। सर, यह जो थ्री नॉट थ्री का आंकड़ा आ रहा है, यह किसी के cold storage से नहीं आ रहा है, किसी के godown से नहीं आ रहा है। सर, मैं अंत में जय हिन्द कहूं, इससे पहले मैं आपके माध्यम से सरकार से हाथ जोड़कर आग्रह करुंगा कि इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं, जब आप दुविधा में होते हैं। Please, मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर request कर रहा हूं कि आप किसानों का दर्द समझिए। सर, पूस की सर्द रातों में, माघ की सर्द रातों में सड़क पर रहना आसान नहीं होता है। किसानों का पानी बंद कर दिया, शौचालय बंद कर दिए। इस तरह की position, इस तरह का aggressive posture हमने तो अपने कुछ पड़ोसी मुल्कों के लिए भी नहीं सुना, जो अंदर तक आ गए। सर, लाल आंखें वहां होनी चाहिए और हम कहां आंखें लाल कर रहे हैं। ये किसान आपके हैं, ये किसान मेरे हैं। अगर इन्होंने एक दिन भी हड़ताल कर दी, एक दिन तय कर लिया कि कुछ नहीं होगा, तो संसद बंद हो जाएगी, सरकारें बंद हो जाएंगी और क्या-क्या होगा कुछ पता नहीं। मैं "जय जवान, जय किसान" और "जय हिन्द" कहूं, इससे पहले आप मुझे बस एक मिनट का समय और दे दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है, आज इतनी सारी चीजें थीं, कई लोग Harold Laski का कथन quote करते हैं। उन्होंने liberty के मसले पर कहा था कि "You need to find the Government accountable time and again. That is the test of the democracy." But we have failed. हमने किसानों को ही fail नहीं किया है। सर, यदि इजाज़त हो, तो तरन्नुम में, नहीं तो यूं ही,

"मैं भी खाइफ़ नहीं, तख्ता-ए-दार से,
मैं भी मंसूर हूं, कह दो अग्यार से,

क्यों डराते हो जिंदाँ की दीवार से,

(जिंदाँ अर्थात् जेल)

"जुल्म की बात को जहल की रात को,
मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।"

धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. Yesterday, we heard a lot of invocations from history from the hon. Leader of the Opposition, and today, Prof. Manoj Kumar Jha warned us against the notion of cherry-picking in history. At the risk of offending both of them, let me invoke something else from history, perhaps, just a footnote. When the Civil Servants from the East India Company used to be sent to India from U.K., or Britain as it was then called, they were given instructions, and one thing they were always told was that for everything that is true about India, the opposite is equally true. I think, it is necessary to point this out in the context of the outpouring of emotion which has happened on the farmers' agitation. Without going into the rights and wrongs of the whole movement and without being judgmental, I just want to place a few facts. The top two lakh farmers of Punjab and Haryana have incomes that are among the top eight per cent of all incomes in India, both urban and rural.

Secondly, Sir, about twenty thousand of them have incomes in the top two per cent. Sir, this is not to berate these people. This is not to take, what the Leftist used to call, the denunciation of the *kulak* classes. This is only to admire their hard work, their integrity, their persistence and their adoption of technology, which they have managed for so long.

Unfortunately, Sir, this is not a situation which prevails in the whole country. I think, if I was to talk about my own State, West Bengal, you will find that for various reasons, also located in history, most of the people who are farmers, kisans are marginal. They undertake subsistence farming. Most of them have land holdings which cannot earn them enough to survive. They need other occupation. On top of that, if we come to the Minimum Support Price, we will find that only between nine and ten per cent of the farmers actually secure the Minimum Support Price and the price differential in rice between the MSP and the price which they get in the market ranges between Rs. 600 and 700 per quintal. That is a colossal sum.

If we were to take what the NABARD had to say, West Bengal ranked 24 out of 29 in terms of monthly income for agricultural households and the same study put the average monthly income for agricultural households at Rs. 1,175/- which is well below the national average. Sir, the reason why I am saying this is that such community need value addition at every point. They need value addition in terms of marketing, they need value addition in terms of agro industries, they need value addition to get organic farming off the ground, and, they need a whole range of investments in the rural sector which have not been forthcoming. Even more than 30 per cent of the vegetables perish due to lack of cold storages and the lack of cold storages can be attributed to the Essential Commodities Act, which has put a certain barrier against hoarding and which was enacted at the time of food shortage.

These are the major constraints and when you have a series of legislations, which put a seal of legitimacy or legal approval on contract farming, which has been done on informal basis today, as Prof. Ram Gopal Yadav pointed out, that legal sanctity which these Acts give, I think, are very, very important in terms of trying to actually lift a community, a whole region which is now being deprived and which falls well short of the achievements which have been there in the Green Revolution.

I urge everyone not to look at the whole country in terms of what the most successful have done but also to look at places where there has been least success. We have, in the course of the Budget, spoken about the possibility, we have got hopes that in the coming years, India will reach double digit growth figures again. That is a very good aspiration to have but this double digit aspiration cannot be achieved if a whole section of the country falls behind. Can you imagine the amount of achievement which we could have if the whole of Eastern India were to actually contribute their 11 to 12 per cent growth, how much it could grow?

Sir, it is not merely a problem of West Bengal; it is a problem which is there in Odisha; it is a problem which is there in Jharkhand, in Assam. The whole region has been suffering. Yesterday, Mr. Prasanna Acharya spoke very eloquently on the need to have a special economic package for Odisha. Earlier, we have heard such a talk from people in Bihar as a result of separation of Jharkhand. It is sometimes difficult to have special packages only for one State at the cost of other. I would urge the Government to look at the possibility of whether the whole of Eastern India can be regarded as a special assistance zone. The reason for it is quite compelling. There are connectivities at every level. I wish to thank, for example, the Chief Minister of

Odisha who sent out his disaster management team during the Amphan crisis in West Bengal. He went out of his way to help in this situation. In every respect, and at a time when people are talking about outsiders and home grown people, etc., we must realise the deep degree of connectivity which exists between all of them. For instance, if we are to talk about coal, we cannot talk about Raniganj without talking about Dhanbad. It is the same thing. We cannot talk about Darjeeling and Dooars without talking about Assam tea. The problems are exactly the same. Steel plant of Durgapur is linked to iron ore of Jamshedpur which is linked to Rourkela. It is all part of the same zone. In the matter of national security, the Left wing extremism which we are confronted with in Odisha are exactly the same in Jharkhand and parts of West Bengal. The problem of illegal immigration which is there in Assam is exactly the same as in West Bengal. Even if we are to look at it in pure spiritual term, I cannot talk about my faith without talking about Jagannath Puri, without talking about Kamakhya, without talking about Baidyanath Dham. It is all part of the same. Today, we are in need of having an integrated approach to the whole eastern region. I was very glad when my friend, Shri Bhubaneswar Kalita, spoke about the Prime Minister coming to Assam 40 times. He later corrected himself in the Central Hall and said it has been 41 times that the Prime Minister has come. That is a colossal number. I dream of the day when in the whole of the eastern region, we can welcome the Prime Minister 41 times. We can dream of a time when the Prime Minister's Kisan Nidhi Samman is available to the 70 lakh farmers of West Bengal which they have been deprived of. We can also look about the time when we can correct the short-sightedness of local politics which deprives people who are already deprived of the Ayushman Bharat Scheme. Sir, India has an integrated approach. We have to take the strong and the weak together, and that is the philosophy of *sabka sath sabka vikas*. I want that philosophy, regardless of party affiliations, to be implemented in this country. If that approach is there, whosoever is there in the State Government does not matter. And I think if we can rise above this basic partisanship and welcome the Centre in the States and the States with each other, we can be looking forward not merely to a 11 per cent growth, but a growth which can be 15 per cent, which can be the envy of the whole world.

I thank you very much for giving me this opportunity to thank the President for his courtesy of this Address.

श्री सभापतिः श्री प्रफुल्ल पटेल। उन्होंने पांच तारीख को बोलने के लिए चिट्ठी भेजी है। श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, I am very grateful to you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address.

Sir, the farmers are agitating on the borders of Delhi. On 20.09.2020, the Bills related to farmers were taken up for consideration. Many speakers, including myself, highlighted the issues related to the Bills. They were related to doing away with the MSP, contract farming, dispute resolution mechanism, etc. After the passage of these Bills, the farmers across the country started their agitation in the national capital and put forth their demands. The Government should be magnanimous enough to consider their demands and come forward to accommodate their demands. Similarly, in the State of Andhra Pradesh, farmers have been agitating for 415 days. They are protesting against the shifting of capital in the State of Andhra Pradesh. Hon. Prime Minister laid the foundation stone of the capital at Amaravati for the residual State of Andhra Pradesh. The construction of new capital is as per the provisions of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. Hon. Prime Minister allocated Rs.1,500 crore for this project. The farmers voluntarily gave their land under the land pooling scheme for the development of new capital city. Around Rs.10,000 crore have already been spent for the construction of new capital city. But the present Government, after assuming the office in the year 2019, abruptly stopped all construction activities pertaining to Amaravati project. The proposal to set up three capitals has been opposed by the people of Andhra Pradesh. Abruptly stopping construction activities in the Amaravati capital and the unfeasible three-capital formula are not only wasting the precious public money allocated by the Central Government but also the amount invested by the State Government and the farmers. The farmers have been agitating for 415 days, but the demand of Amaravati farmers is not being considered either by the State Government or the Central Government. It is high time for the Government to consider the demand of agitating farmers and come up with a better solution.

Similarly, Polavaram Project is also a national project declared in the Andhra Pradesh Reorganisation Act. During the rule of earlier Government, 69-71 per cent work had already been completed. The rest of the project has to be completed. For that purpose, under the guise of reverse tendering, the present Government abruptly stopped the construction of Polavaram Project and wasted one year. Also, crop of one year is being wasted for local farmers. The project is now in doldrums. The

project has been delayed and the project completion date keeps on extending. The rehabilitation and resettlement package is very minimal. The State Government is not taking proper steps to give serious thought to it as the incumbent Chief Minister is involved in so many CBI and ED cases which are being inquired into and are pending before the court of law. It is high time for the Central Government to intervene and allocate funds to the Polavaram Project. It has to be seen that the project is completed within a specified time to do justice to the farmers and the people of the State of Andhra Pradesh.

For Vijayawada and Visakhapatnam Metro Rail Projects, funds have not been allocated. In the President's Address importance has to be attached to infrastructure and transport. I would like to draw the attention of the Government towards the fate of Vijayawada and Visakhapatnam Metro Rail Projects. Both the metro services are a non-starter in the State of Andhra Pradesh. I seek a clarification in this regard.

Sir, recently the State Government passed an Ordinance effecting major changes in the Municipal Corporation Act, 1964. This has been done in the spirit of local self-government. But here the ulterior motive is to secure more loans from the Central Government.

Sir, I would like to mention about the very pathetic conditions prevailing in the State of Andhra Pradesh. The Central Government is allocating huge amounts of funds under various schemes but the present Government in the State of Andhra Pradesh is diverting the funds for some reasons and there is total mess in the financial management of the State of Andhra Pradesh. The State is under severe financial stress. The situation has worsened to such an extent that the State Government of Andhra Pradesh finds it very difficult to even pay the salaries of the Government employees. There is no mention of it in the President's Address. The present State Government has borrowed Rs.1,46,000 crore during these 20 months. Likewise, there is law and order problem in the State of Andhra Pradesh. The Government is filing cases against persons who criticize and bring things to the notice of the Government. The Government is implicating them in false cases. Another important issue is that there are attacks on temples; there is also a forcible* There was a temple chariot in Antarvedi.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: Mr. Ravindra Kumar, you have two minutes.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Okay, Sir. There is also attack on democratic institutions. Recently, the Government also directly made an attack on judiciary. In this connection, proceedings are pending in court and the Division Bench of the High Court has made some observations. It is also relevant to state this thing at this juncture and to bring to the notice of this constitutional body. I wish to bring it to the notice of this House. The hon. High Court has made an observation, to some extent, after getting success in overreaching and undermining two constitutional bodies, the Legislative Council and the State Election Commission, it was the turn of the highest court in the State of Andhra Pradesh, that is, the Andhra Pradesh High Court. With a view to protecting the rights of citizens, the Andhra Pradesh High Court has passed a number of orders setting aside incorrect and unsustainable orders passed by the Government of Andhra Pradesh in the month of April, 2020, the Division Bench of the hon. High Court quashed the Government orders regarding introduction of English medium in schools as compulsory subject. Thereafter, social media was flooded with insulting and even abusive posts against hon. Judges of the court. Even the High Court was not spared. Further, the Chief Minister himself has written a confidential letter to the Chief Justice.

MR. CHAIRMAN: Please don't quote the Chief Minister.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, it is the observation of the court. It is not by me. Now, there is a situation prevailing in the State of Andhra Pradesh. It is not my dialogue. It is the dialogue of the Division Bench. It is an observation made by the hon. Division Bench. There is an alarming situation in the State of Andhra Pradesh. I request the Centre to look into and concentrate on it.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, one final sentence. It is stated, "Till the publication of letter of the Chief Minister, I was not having much information about him. But immediately thereafter, I became curious to know about it. * Accordingly, I did the same thing and thereafter I got very disturbing information."

---

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, it is needless to state that there is an attempt of highly placed persons in media detrimental to the interest of a democratic state as guided by rule of law. A person, who is under the cloud of charges in a criminal court, is provided with authority of law, to pursue his anger on an organ of the State, that is, judiciary. His conduct should certainly be a debate before the constitutional courts for his continuance and his decisions taken during this period of governance.

MR. CHAIRMAN: I have given you two minutes. I have also cautioned you. You should conclude. Please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Okay, Sir. It would certainly have a bearing on the society at large. Perhaps these factors may have to be considered for assessing the conduct of popular Government in the State of Andhra Pradesh. Therefore, I request the Central Government and the hon. Prime Minister that it is high time to consider all these aspects and to set right the things which are going on in the State of Andhra Pradesh under the premise of popular Government. Thank you.

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुझे एक मौका दिया।

सभापति महोदय, 2020 पूरे विश्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है, जिसमें हमने कई उतार-चढ़ाव, कई निराशा और बुलंद हौसला, दुख-खुशी की भावनाओं का अनुभव किया, लेकिन आज ठीक एक साल बाद तेजी से गिरते हुए कोरोना के संक्रमितों के आँकड़ों को देख कर देश में एक नई उमंग और एक नया जोश भर कर आ चुका है। जनवरी 22 से 28 तक 146 ऐसे जिले हैं, जहाँ एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ है। हमारा भारत एक अमर पक्षी के रूप में कोरोना की राख से उठ रहा है। कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद में भारत की इस अद्भुत सफलता पर, हमने जो चुनौतियों का सामना किया, और उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की कार्यनीति पर और उसी के साथ पुनरुज्जीवित भारत की एक नई छवि पर प्रकाश डाला। हर साल की तरह इस साल भी उनसे राष्ट्र को एक नया मार्गदर्शन मिला। उसी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता और मार्ग प्रशस्त हुआ तथा हम सबको राष्ट्रपति महोदय से मूल्यों-सिद्धांतों की बुनियाद पर एकजुट होकर एक नया इतिहास रचने और नई बुलंदियों को छूने की प्रेरणा भी मिली है। मैं तहेदिल से उन्हें धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, कोरोना एक अदृश्य शत्रु था, जिसका मुकाबला करने के लिए भारत के पास केवल दो शक्तियाँ थीं। हमारी पहली शक्ति थी भारत के प्रधान सेवक और रक्षक, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसके आधार पर सभी प्रयासों को एक ही मुट्ठी में बाँधना, 36 राज्यों को एक ही माला में पिरो कर भारत का मार्ग प्रशस्त करना, इस कोरोना की महामारी के लिए एक युद्ध स्तर की रणनीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि 150 देशों के लिए एक विश्व साझा अभियान का नेतृत्व करना, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। शुरुआत में कई विशेषज्ञों ने, और यह वास्तविकता भी थी, कई भयंकर अनुमान लगाए थे - 80 करोड़ लोग संक्रमित होंगे, 20 लाख जानें जाएँगी। लेकिन अगर मैं क्रिकेट का एक उदाहरण दे पाऊँ, चूँकि मैं क्रिकेट का एक प्रेमी भी हूँ, तो भारत ने कोरोना के bouncer पर एक hook shot लगा कर boundary को भी पार करा दिया है। विश्व में average global recovery rate 70 प्रतिशत है, लेकिन भारत की recovery rate 97 प्रतिशत है, जो विश्व में सबसे बड़ा आँकड़ा है। इसी के साथ वह दूसरी wave भारत को छू भी नहीं सकी। उसके पीछे कारण यह था कि नेतृत्व ने सही समय पर सही निर्णय लिया। हमने विदेशी नागरिकों के वीज़ाओं को निलंबित किया, हमने स्फूर्ति से lockdown लागू किया, ताकि 37 लाख जानें बच पाएँ। और उसी के साथ प्रधान मंत्री जी ने कहा था, 'जान है, तो जहान है'। महासंकट के वित्तीय बोझ की चिंता न करते हुए और सभी को आर्थिक मार से बचाने के लिए सरकार ने, चाहे नौजवान हो, किसान हो, युवा हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, सीधा उनके अकाउंट में राशि पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

सभापति महोदय, एक यह लॉकडाउन था, जहां एक व्यक्ति के आह्वान पर, एक ही व्यक्ति के अनुरोध पर पूरे देश की जनता ने स्वेच्छा से उस आह्वान और उस अनुरोध का पालन किया, वहीं दूसरी तरफ, एक वह लॉकडाउन था, जब 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी। वह लॉकडाउन देश की जनता पर थोपा गया था और पूरे देश को जेलखाना बना दिया गया था।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*...

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सभापति महोदय, यह बात मैं जिस तरह यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं, उसी तरह वहां पर खड़े होकर भी कहता था। सत्य, सत्य ही होता है और उसके पीछे न तो आपको छुपना चाहिए और न ही देश की जनता आपको छुपने देगी।

सभापति महोदय, कोरोना के शुरुआती समय में भारत पीपीई किट नहीं बना पाता था, लेकिन 60 दिन के अंदर ही हमने पीपीई किट का केवल उत्पादन ही नहीं किया, बल्कि पीपीई किट के उत्पादन में आज भारत विश्व का द्वितीय उत्पादक देश बन गया है। भारत में ही आज वेंटिलेटर्स का उत्पादन हो रहा है। विश्व में वैक्सीन बनाने में दस साल लग जाते थे, लेकिन आज हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने एक साल के अन्दर ही देसी वैक्सीन बना कर, भारत का नाम पूरे विश्व में उजागर किया है। केवल यही नहीं, वैक्सीन बनने के बाद विश्व स्तर पर सबसे तेज़ टीकाकरण अभियान शुरू किया गया और फेज़-1 में ही 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने

के लक्ष्य से इसकी शुरुआत की गई। यह कारगर और किफ़ायती वैक्सीन केवल भारत के लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि आज यह 'Vaccine for humanity' बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के Secretary General, Mr. António Guterres ने स्वयं कहा है कि भारत में टीका उत्पादन की क्षमता पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा वरदान बन चुकी है। I would like to quote him. He has said, 'The production capacity of India is the best asset that the world has today'.

महोदय, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना भारत के मूल्यों एवं सिद्धांतों को अभिव्यक्त करती है और भारत ने अपने उन मूल्यों और सिद्धांतों का पूर्ण रूप से अनुसरण किया है। भारत की इस सफलता के पीछे जो दूसरे बड़े हथियार हैं, वे हैं भारत की सामूहिक शक्ति अथवा सामर्थ्य, हमारा अतुल्य वैज्ञानिक गढ़, वैक्सीन के ट्रायल के हमारे वालंटियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज़, हमारी एनजीओज़, हमारी पुलिस फोर्स के कर्मी और हमारे जवान। इन सबने अपनी जान को जोखिम में डाल कर हम सबकी जानों की रक्षा की। अगर ये सब न होते, तो आज हम भी न होते।

सभापति महोदय, आज इस सदन में मैं उन लोगों के लिए कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहता हूं:-

'न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है,
जज़्बा है जन-सेवा का मन में, सफ़र निरन्तर जारी है'।।

सभापति महोदय, जहां एक तरफ कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व का केन्द्र बिन्दु बन गया और विश्व की सारी शक्तियां इस विश्वव्यापी विपदा के निवारण में लग गईं, वहीं दूसरी तरफ चाहे अर्थव्यवस्था हो, व्यापार हो, आजीविका हो, ये सब पूरे तरीके से नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए।

10.00 A.M.

भारत भी टेक्निकल रिसेशन की खाई में जा रहा था। मैं दाद देता हूं हमारी सरकार को, कि छः महीने के अंदर वापस भारत को रिकवरी की पटरी पर नरेन्द्र मोदी जी की एनडीए की सरकार लेकर आई है। आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं कि जनवरी के माह का जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये था, जो राजस्व संग्रह का एक नया इतिहास बना है। दूसरी तिमाही में जीडीपी नेगेटिव साढ़े सात प्रतिशत तक सीमित हो गई, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है, जो आज हमारे सांसद महोदय स्वपन दासगुप्ता जी ने भी कहा कि इस वर्ष साढ़े 11 प्रतिशत ग्रोथ रेट जीडीपी की रहेगी और इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड, आईएमएफ ने भी कहा है कि एक वर्ष के अंदर भारत सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व पटल पर उभरने की क्षमता रखता है। हमारी पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का एक टारगेट है, उस पर हम अडिग हैं। उसी के साथ पांच मिनी बजट हमने कोरोना के समय में निकाले थे और कई क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया था, मदद दी थी और पोस्ट कोविड ऑर्डर में भी उन क्षेत्रों को उभारने का हमारा संकल्प है। इससे यह साबित होता है कि कोई भी आपत्ति या विपत्ति आई, चाहे वह प्राकृतिक हो, चाहे किसी तरीके की भी विपत्ति हो, हमारी 130 करोड़ जनता, हमारे भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कभी भी प्रभावित

नहीं हो सकता। लेकिन इसी के साथ थोड़ा दुख भी होता है कि जहां एक तरफ देश की जनता, हमारे जनसेवक, हमारी सरकार इस कोरोना की महामारी का सामना कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के कई नेता केवल सवाल उठाने में और टीका-टिप्पणी करने में रुचि रख रहे थे। **..(व्यवधान)...** सही बात है, क्षमता रखनी होगी, जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा - सुनाने में भी और सुनने में भी।

सभापति महोदय, पहले लॉकडाउन पर प्रश्न उठे कि लॉकडाउन क्यों, कितने दिन, आपने किससे पूछकर किया? उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस पर प्रश्न - अनलॉक क्यों, कब होगा, कैसे होगा, आपने किससे पूछकर किया? कांग्रेस पार्टी के इस सदन के उप नेता, श्री आनन्द शर्मा जी ने, जो गृह मंत्रालय की संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं अपनी रिपोर्ट में सरकार की सराहना की है, सरकार की प्रशंसा की है और मैं उनको दाद देता हूं कि कोई तो है जो सही बोल रहा है।

मैं क्वोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है - "The Committee appreciates the efforts made by the Government for the management of Covid-19 pandemic. The lockdown gave the country time to ramp up its public infrastructure, build the capacity of hospital and health workers." इसके बाद भी हमारे कई प्रतिपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग पर प्रश्न उठाये। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए फेज़-3 ट्रायल समाप्त होने के पहले अनुमति प्रदान कर सकते हैं तो क्या हमारी सरकार देश की जनता की जान बचाने के लिए देश में आपातकालीन परमिशन क्यों नहीं दे सकती? एक नेता जी ने तो इतना भी कहा है और मैं उन्हें क्वोट करना चाहता हूं - "भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन हम नहीं लेंगे।" वैक्सीन का भी एक राजनीतिक रंग होता है! स्वास्थ्य का भी एक राजनीतिक रंग होता है! मुझे तो आश्चर्य होता है। इसके बाद विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि ठीक है, आपातकालीन उपयोग की अनुमति आपने प्रदान कर दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक ढांचा हमारे देश में हमारे पास नहीं है। तो मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि जब यूपीए सरकार थी, तब सभापति महोदय, एक साल का नहीं, पाँच सालों का जो स्वास्थ्य का बजट था, वह 1 लाख, 44 हज़ार करोड़ रुपये था। उन पाँच सालों में इस बजट को भी पूरी तरह से खर्च नहीं किया गया, केवल 1 लाख, 26 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किये गये, मतलब 15 प्रतिशत कम खर्च किया और आज ढाँचे की बात की जा रही है! 2013 में तो 18 प्रतिशत under utilization रहा। वहीं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की एनडीए की सरकार के 4 साल में हर साल जो बजट का आवंटन रहा, वह कई गुना ज्यादा रहा। उस बजट के आवंटन से 2 से 9 प्रतिशत ज्यादा खर्च हर साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया। 'स्वस्थ भारत', 'शिक्षित भारत' हो, तभी भारत 21वीं सदी का नेतृत्व कर पायेगा।

इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि यह कहानी यहाँ नहीं रुकती। महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, इस साल के बजट को देख कर आपको भी आश्चर्य होगा कि पाँच साल का यूपीए

सरकार का स्वास्थ्य बजट 1 लाख, 44 हज़ार करोड़ रहा और एनडीए सरकार का एक साल का, इस वर्ष का स्वास्थ्य बजट 2 लाख, 23 हज़ार करोड़ है। सभापति महोदय, इसमें पिछले वर्ष से 137 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 22 नये एम्स बनने जा रहे हैं। 'प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत 1.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज मिला। सभापति महोदय, 'स्वस्थ भारत', 'आयुष्मान भारत', 'Fit India', ये केवल मुहिम नहीं हैं, ये आने वाले समय में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार और असरदार बनाने के यंत्र हैं।

सभापति महोदय, एक विषय पूरे भारत में आज चिन्ता का विषय बना है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने गाँव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, बल्कि आज किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। सभापति महोदय, इसी सोच और विचार के साथ हमारी सरकार ये तीन कृषि कानून लेकर आयी है, ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नयी प्रगति हो। जो राजनीतिक आज़ादी हमें 70 साल पूर्व मिली थी, लेकिन 70 साल से किसान जिन बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़ कर उसे आर्थिक आजादी, विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना- यह एनडीए सरकार का, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। किसान की आय दोगुनी हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वह देश में अपना उत्पादन कहीं भी बेच पाये, एक ही जगह तक वह किसान सीमित न हो, इसलिए ये कानून लाये गये। संवाद जरूर होना चाहिए, जैसा मेरे भाई मनोज जी ने कहा। 11 बार सरकार ने संवाद किया है, जब deadlock हुआ है, तब सरकार ने यह भी कहा है कि तीनों कानूनों को हम 18 महीनों के लिए स्थगित करेंगे, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिन लोगों ने ऐसे ही कानून की वकालत की थी, आज वे क्या कह रहे हैं? सभापति महोदय, अगर हम कांग्रेस पार्टी का 2019 का चुनाव घोषणापत्र पढ़ें -मैं इसे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ - इस चुनाव घोषणापत्र के अंक नंबर 11 में जो लिखा है, मैं उसको quote करता हूँ ,"Congress will repeal, I repeat, will repeal the Agricultural Produce Market Committees Act and make trade in agricultural produce including exports and inter-state trade free, I repeat, free from all restrictions". उस समय के हमारे कृषि मंत्री जी ,परम आदरणीय शरद पवार जी ने 2010 और 2011में इसी संदर्भ में हर एक मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। मैं वह quote करना चाहता हूँ ,जो शरद पवार जी ने हर एक मुख्य मंत्री को चिट्ठी में लिखा था। "As you are aware, the agriculture sector needs well functioning markets to drive growth, employment and economic prosperity in rural areas of the country. This requires huge investments in marketing infrastructure, including cold chain and for this private sector participation is essential, I repeat, and for this private sector participation is essential",निजी क्षेत्र का निवेश अनिवार्य है, "for which a policy environment needs to be in place. In this context, the need to amend the present State APMC Act on the lines of Model State Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act 2003 to encourage the private sector, I repeat, the private sector in providing alternative competitive

marketing channels in the overall interest of farmers/producers and consumers cannot be overemphasized". ...**(व्यवधान)**... सहमति है।

श्री सभापति : प्लीज़, प्लीज़।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है, तो आप जरूर बताएँ। कई चीज़ों में सहमति होनी चाहिए।...**(व्यवधान)**... सभापति महोदयहमें यह ज़ुबान बदलने की , ...**(व्यवधान)**...आदत बंद करनी होगी।

श्री सभापति : प्लीज़, प्लीज़।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : चित भी मेरी और पट भी मेरी,...**(व्यवधान)**... यह कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? जो आपने तब कहा था, उस पर आप अडिग रहेंगे, तो आपका भी मान-सम्मान बढ़ेगा।...**(व्यवधान)**... Hypocrisy would not have been there if you had not done hypocrisy with the people. Please understand that.

MR. CHAIRMAN: Let us not get into personal comments.

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सभापति महोदय, जिस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत से डेढ़ गुना बढ़ोतरी की हो, जिस सरकार ने गेहूँ के भुगतान में, 2013-14 में जो 34 हज़ार करोड़ रुपए किसानों का भुगतान होता था, उसे पाँच साल के अंदर डबल से ज्यादा करके 75 हज़ार करोड़ रुपए किया हो, जिस सरकार ने दाल के मुद्दे पर, 2013-14 में जो केवल 236 करोड़ रुपए का देश के सारे किसानों को भुगतान किया गया था, उस 236 करोड़ रुपए को 40 गुना बढ़ा कर 10,550 करोड़ रुपए किया हो, जिस सरकार ने हमारे महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश के कपास के किसानों के लिए जो 2013-14 में केवल 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, उसको 300 गुना बढ़ा कर 26 हज़ार करोड़ रुपए किया हो, जिस सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए 6 हज़ार रुपए हर साल के हिसाब से 1,13,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुँचाये हों, जिस सरकार ने कृषि की अधोसंरचना के लिए एक लाख करोड़ रुपए का नया फंड तैयार किया हो, जिस सरकार ने फसल के नुकसान के लिए 'फसल बीमा योजना' लागू करके 5 साल के अंदर 90 हज़ार करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में किसानों के खाते में पहुँचाए हों, वह सरकार किसानों के विकास और प्रगति के लिए कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है और कटिबद्ध रहेगी। सभापति महोदय, 26 जनवरी को जो घटना घटी, जो गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए एक गौरव का दिवस होता है, उस दिन के वे घातक दृश्य एक दर्दनाक याद बन चुके हैं। उस दौरान 394 पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को घायल किया गया, एक किसान ने अपनी जान गंवाई, राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर पुलिसकर्मियों को पीटा गया, उनको कुएं में फेंका गया और राजधानी के कई हिस्सों को तहस-नहस कर दिया गया। उसके बाद भी जब यह सदन मिला, तब हमारे विपक्ष ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का boycott करके राष्ट्रपति जी का, देश का और इस लोकतंत्र का

तिरस्कार किया है। आज मनोज कुमार झा जी ने कहा था कि हमें सुनना भी होगा और सुनाना भी होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि सुनाने के लिए तो आप आ गए, लेकिन सुनने के लिए आप नहीं आए थे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की बात कर रहा था। सभापति महोदय, एक तरफ पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा था, पूरा विश्व विकास के एजेंडे को दरकिनार करके इस महामारी और प्रलय का सामना कर रहा था, इसमें सारे संसाधन झोंक दिए थे और दूसरी तरफ भारत में एक क्रमबद्ध प्रधान सेवक ने, जिनकी पार्टी का नारा "सबका साथ, सबका विकास" है, उस संकट को सुधारने के लिए केवल कार्य ही नहीं किए, बल्कि उस समय में विकास करने के अवसर भी ढूंढ़ लिए। हमारे पूर्वजों का एक आज़ाद भारत का, स्वराज का सपना था और आज एक आत्मनिर्भर भारत का सपना है, देश को विश्व पटल पर उजागर करने का सपना है। हमारे महाभारत में लिखा गया है -

"अपि शाकं पचानस्य सुखं वै मघवन गृहे।
अर्जितं स्वेन वीर्येण न व्यपाश्रित्य कञ्चन॥"

सभापति महोदय, इसका सार है कि किसी दूसरे पर बोझ बनने के बजाय अपनी मेहनत से कमाया गया फल कहीं ज्यादा सुखदायी होता है और यह तभी मुमकिन होता है, जब कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी हमारे भारत में आत्मनिर्भर बन पाएगा। "आत्मनिर्भर भारत" की आत्मा किसान, युवा, आम जनता के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इस महाप्रलय के समय में हमारी सरकार ने "गरीब कल्याण रोज़गार अभियान" के तहत 2,76,000 करोड़ का क्रियान्वयन किया।

श्री सभापति : ज्योतिरादित्य जी, आपकी पार्टी ने आपको जो समय दिया, वह समाप्त हो रहा है।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सर, मैं पाँच मिनट और बोलना चाहता हूँ।

श्री सभापति : ठीक है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): We have allotted him extra time.

MR. CHAIRMAN: Your Party has got time, they have agreed; five minutes more, please.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Thank you, Sir. I will not take more than five minutes.

सर, 80 करोड़ गरीबों को आठ महीने तक निशुल्क राशन प्रदान किया गया। "वन नेशन, वन राशन कार्ड" लाकर एक नया इतिहास रचा। "प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना" के तहत महिलाओं को 14 करोड़ मुफ्त गैस सिलेंडर्स पहुंचाए। सभापति महोदय, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि सरकार का लक्ष्य अन्त्योदय है, सरकार का प्रण अन्त्योदय है और सरकार का पथ अन्त्योदय है। सभापति महोदय, शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है, जिसके आधार पर हम अपने मानव संसाधन को मानव पूँजी में परिवर्तित कर सकते हैं। हम 34 साल बाद नई शिक्षा प्रणाली लेकर आए हैं और उसमें हम लोग शिक्षा के नए रूप, नई सोच, नए स्किल्स से एक नए भारत को उबारने की कोशिश करेंगे। सभापति महोदय, 2021 का भारत, 2013 का भारत नहीं है। यहाँ SMEs को MNCs में परिवर्तित करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। हमने उन SMEs को 20,000 करोड़ का सरल ऋण दिलवाया है, हमने SMEs की परिभाषा 14 साल बाद बदली है और भारत को एक global manufacturing hub में परिवर्तित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं।

सभापति महोदय, यह वर्ष केवल संकट का नहीं है, बल्कि यह सबसे ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें शेष था - इंडिया को भारत से जोड़ना, हमारी पुरानी संस्कृति को पुनर्जागृत करना और श्रीराम जन्म-भूमि के भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि विश्व के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की राष्ट्रीयता की भावना और उनके ओजस्वी नेतृत्व का परिणाम है कि अब राम मंदिर का निर्माण नये भारत के निर्माण का प्रतीक बनेगा। मैं उनके शब्दों में कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था,"राष्ट्र को जोड़ने का, स्व को संस्कार से जोड़ने का कार्य संपन्न होगा।" सत्य, अहिंसा, आस्था, वसुधैव कुटुम्बकम्, विविधता में एकता, बलिदान, ये हमारे देश के वे मनके हैं, जिनको हज़ारों साल से सभी भारतीयों ने एक माला में पिरोकर रखा है। एक नया भारत पुराने मूल्यों के अभाव में खड़ा नहीं हो सकता। हमारा राम मंदिर आधुनिक भारत की मजबूत नींव का प्रतीक होगा, जिसकी विविधता में एकता भी होगी और समता भी होगी।

जहाँ एक तरफ यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का ताज और शान, जम्मू-कश्मीर, जहाँ हर देशवासी का दिल बसता है, उसको बेड़ियों से मुक्त करके राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कदम उठाया गया, जब अनुच्छेद 370 को हमने रद्द किया। उस अनुच्छेद से केवल हानि हो रही थी- अलगाववाद, आतंकवाद, व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार। जब यह रद्द किया गया, उसके ठीक बाद "आयुष्मान भारत" के तहत यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज के संरक्षण में डेढ़ करोड़ जनता को लिया गया। हर एक नागरिक को केन्द्र सरकार की बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल पाया। इसका संदर्भ कल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी दिया कि 70 साल के इतिहास में पहली बार जिला विकास परिषद् (डीडीसी) का चुनाव हमारी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आयोजित किया। सभापति महोदय, सरकारें आईं भी और गईं भी, लेकिन जो स्वप्न सरदार वल्लभभाई पटेल ने देखा था, जो स्वप्न बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था, 'एक विधान, एक प्रधान और एक निशान' का स्वप्न, जो डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था,

'कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत' का सपना, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसे मोदी सरकार ने पूरा करके दिखाया है।

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोरोना का महाप्रलय, जो विकास के पथ को कुचलने आया था, उसका सामना हमारी सरकार ने एक बुलंद ढाल की तरह किया और विपत्ति को भी अवसर में बदलकर, reforms की झड़ी लगाकर, "न हम रुकेंगे और न भारत रुकेगा", माननीय राष्ट्रपति जी की सोच और विचारधारा के आधार पर देश का मार्ग प्रशस्त किया है। सभापति महोदय, केन्द्र में दो बार भारी बहुमत, उत्तर प्रदेश से कर्णाटक, असम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, बिहार तक जो असीम आशीर्वाद चुनाव में जनता का मिला है, यह आशीर्वाद इस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पूँजी है और यह तभी संभव हो पाया है, जब एक प्रभावी छवि, असरदार नीति और भारत के लिए विज़न का क्रियान्वयन हमारी सरकार ने किया है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। भारत एक नई सामर्थ्य के साथ इस कोरोना काल से उभर रहा है।

"हज़ार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उठें,
वो फूल खिल के रहेंगे, जो खिलने वाले हैं।"

श्री सभापति:दिग्विजय सिंह जी। मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया, लिस्ट में जो नाम आया, मैंने उसी के हिसाब से अनुमति दी है।

श्री दिग्विजय सिंह(मध्य प्रदेश):सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। वे जितने अच्छे ढंग से यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतने ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: सर, आपका आशीर्वाद है।

श्री दिग्विजय सिंह:वह हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहें, आगे भी जहां हों, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा।

सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध इसलिए करता हूं, क्योंकि इसमें वास्तविकता का उल्लेख कहीं नहीं है। वर्ष 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के शुद्ध बहुमत के आधार पर प्रधान मंत्री चुना गया। इन 6-7 वर्षों में उन्होंने क्या-क्या वायदे किये थे और क्या-क्या वायदे निभाये, इसका कहीं उल्लेख नहीं है, विदेशों से काला धन आएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी बनेगी, इसका कही उल्लेख नहीं है, 2 करोड़ रोज़गार मिलेंगे, इसका कहीं उल्लेख नहीं है, बेहतर अर्थव्यवस्था होगी, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। उल्लेख तो है, लेकिन गलत आंकड़े दिये गये। उन्होंने maximum Government and minimum governance का पालन किया, क्योंकि total

governance आज पीएमओ केपास है, बाकी मंत्रियों केहाल आप जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि रोज़गार नहीं मिला, काला धन नहीं आया, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हुई, इन सब बातों का उल्लेख राष्ट्रपति जी केअभिभाषण में नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था global recession केबाद धीरे-धीरे सुधरने लगी थी। वर्ष 2014 केबाद पहला निर्णय नरेन्द्र मोदी जी ने नोटबंदी का लिया और उस नोटबंदी में डा. मनमोहन सिंह जी का राज्य सभा केसदन में जो बयान था, "It is a monumental mismanagement, will hurt small industry, unorganised sector, agriculture and the poor. It is an organised loot and legalised plunder and there will be two per cent drop in the GDP."

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA) *in the Chair.*]

उन्होंने जो कहा था, उनकी एक-एक बात सही निकली। नोटबंदी केलिए यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, fake currency समाप्त हो जाएगी। उस समय digital trading की वकालत माननीय प्रधान मंत्री जी ने की थी, उस समय circulation of currency साढ़े सत्रह लाख करोड़ रुपये का था। आज वषर2021 में circulation of currency has gone up to Rs. 27.8 lakh crores. What has happened, hon. Prime Minister? Will you please answer? Hon. Finance Minister, will you please give us the details? अथ यवस्था बिगड़ी, 50 लाख लोगों को बेरोज़गार होना पड़ा। नौकरियां गईं, MSMEs और unorganized sectors पूरे तरीकेसे बरबाद हो गए और आज तक वे उठ नहीं पाए हैं। आप लोग कानून लाए, क्योंकि यह आपकेएजेंडे में था कि धारा 370 समाप्त करेंगे, आपने कि कया। जब अटल जी से कशमीर समसया केबारे में पूछा गया कि इसका हल कया है, तो उन्होंने कहा कि इसका हल जमहूरियत, कशमीरियत और इंसानियत है। जब आप धारा 370 का कानून लाए, तो कहीं भी किसी भी प्रकार न जमहूरियत नज़र आई, न इंसानियत नज़र आई और न कशमीरियत नजर आई। कया आतंकवाद समाप्त हो गया? आज भी आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है । यदि आप आंकड़े देखेंगे, तो पिछले वर्षों की अपेकषा कहीं ज्यादा लोग आतंकवाद की गितिविधयों से आहत हुए हैं, हमारे security personnel आहत हुए हैं। कशमीर घाटी केलीडसर, कि जन्होंने भारतीय संविधान केअंतगरत हमेशा चुनाव लड़े, सरकारें बनाईं, आपने उन सब लोगों को जेल में बंद कर दिया। कया यही जमूहरियत है, यही इंसानियत है और यही कशमीरियत है? आप CAA और NRC लाए। ठीक है, आपकेपास बहुमत है, इसिलए आप लाए, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि 'सबका साथ, सबका विकास'। उन्होंने 2019 में इसमें जोड़ दिया 'सबका कि वशवास'। मैं पूछना चाहता हूं कि कया CAA और NRC लागू करने केलिए इस देश केलोगों का कि वशवास लिया? कया उनहोंने उन वर्गों का विशवास लिया, जो कई दिनों तक ठंड में आंदोलन करते रहे? यिद आज आप देखेंगे, तो पूरे तरीकेसे यह सरकार धीरे-धीरे विशवास खोती जा रही है।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यहां सिंधिया जी ने और हमारे मित्रों ने बहुत सी बातें कोरोना वायरस के बारे में कही हैं। चाइना में पहला केस दिसम्बर, 2019 में डिटेक्ट हुआ था। भारत में जनवरी, 2020 में केरल में केस डिडेक्ट हुआ और उसकी डेथ हुई। राहुल जी ने 12

फरवरी, 2020 को यह बयान दिया था कि ये पेंडेमिक आ रहा है, होशियार हो जाइए। फिर उन्होंने 3 मार्च, 2020 को दोहराया कि आप सचेत हो जाइए और इसकी तैयारी करिए। इनके बयान का मखौल उड़ाया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पार्लियामेंट में 5 मार्च को कहा कि घबराने की बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। महोदय, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि हमने केवल चाइना और Hong Kong से आने वाले लोगों की screening की, लेकिन उस समय तक 20 राष्ट्रों में कोरोना के केस आ चुके थे, रिपोर्ट हो चुके थे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के लिए 'नमस्ते ट्रम्प' का आयोजन करना जरूरी समझा। 24 व 25 फरवरी को उस देश से जहां पर कोरोना वायरस के केसेज़ थे, लाखों लोगों को 'नमस्ते ट्रम्प' के नाम पर इकट्ठा किया गया। अहमदाबाद की झुग्गी-झोंपड़ियों को न देख पाएं, इसके लिए दीवार खड़ी करा दी गई।

मैं माननीय सिंधिया जी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, आप उसका उल्लेख कर रहे थे। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 2018 का चुनाव आप और हम सब लोगों ने मिलकर लड़ा था, वे किन कारणों से पार्टी छोड़कर भाजपा की शरण में गए, मैं नहीं जानता, वे ज्यादा जानते हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के प्रकोप को क्यों टाला? उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए उनको समय चाहिए था। जिस दिन उनकी सरकार बन गई, उस दिन उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने से पहले, जनता कर्फ्यू, थाली पीटिए, दीया जलाइए, घंटी बजाइए, उससे कोरोना वायरस 21 दिन में चला जाएगा। महाभारत 18 दिन में जीते थे। यदि इस सोच का प्रधान मंत्री इस देश में हो, तो इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने लॉकडाउन लगाया - सिंगापुर जैसे राष्ट्र ने लॉकडाउन लगाने के लिए आठ दिन का समय दिया, लेकिन भारतवर्ष के अंदर केवल चार घंटे का समय दिया गया। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पूरे तरीके से Federal structure के खिलाफ हैं, मेरा यह आरोप है। शायद सिंधिया जी चले गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने मुख्यमंत्रियों और राज्यों से चर्चा किए बिना 130 करोड़ की जनता के देश में लॉकडाउन लगाने के लिए चार घंटे का समय दिया और आपने सूचित भी नहीं किया। उसका हश्र यह हुआ कि पूरे देश में migrant labour परेशान हो गई। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि 21 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 21 दिन बिता लेंगे। जब उन्हें लगा कि अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं - क्योंकि उनके पास न तो खाने के लिए, न रहने के लिए, न पीने के लिए और न ही किराए के लिए पैसे थे, रेल भी नहीं चल रही थी और न ही सड़क पर बसें थीं, तो वे क्या करते - तब लाखों लोग पैदल निकल पड़े और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। गर्भवती महिलाओं के बच्चे पैदा हो गए। कुछ लोग पैदल चले गए और एक महिला तो अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर झारखंड तक ले गई। आप यदि लॉकडाउन के लिए सात-आठ दिन का समय दे देते, तो शायद यह मुसीबत नहीं आती। आप थाली बजाने के बजाय, घंटी बजाने के बजाय यह कह देते कि हम फलां तारीख से लॉकडाउन करने जा रहे हैं, आप सब अपने घर चले जाइए। स्टूडेंट्स फंस गए, यात्री फंस गए, टूरिस्ट्स फंस गए और जो हालात हुए, वे आप देख रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने 20 लाख करोड़ रुपये का Rehabilitation Package दिया। दूसरे विकसित देशों ने उसको ग्रांट के रूप में दिया, लेकिन आपने लोन के रूप

में दिया। यह एप्रोच गलत थी। वित्त मंत्री महोदया, मेरा आपसे यह कहना था कि यदि आपका Demand Stimulus का पैकेज होता, तो हालात सुधरते। इस समय लोगों को उनके हाथ में पैसों की आवश्यकता थी, लोन की आवश्यकता नहीं थी। उनको आज आवश्यकता इस बात की थी कि किस प्रकार से हम लोग उनके हाथ में पैसा दें। इसलिए राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप "न्याय योजना" के अंतर्गत जिस तरह हमने प्रस्तावित किया था, उस "न्याय योजना" के अंतर्गत गरीब, मज़दूरों और बेरोज़गारों के हाथ में पैसा दे दीजिए, जिससे वे अपना परिवार चला लेंगे। वह आपने नहीं दिया, जिसकी वजह से काफी दिक्कत और परेशानी आई।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपदा में अवसर निकालना मोदी जी खूब अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी आपदा में अवसर निकालने में खूब माहिर है। पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स खरीदने में बड़े पैमाने पर * हुए। जब हमारा पहले से प्रधान मंत्री रिलीफ फंड था, तो अलग से पी.एम. केयर्स फंड बनाने की आवश्यकता क्या थी? उसमें न तो हम आर.टी.आई. से जवाब मांग सकते हैं और न ही उसके बारे में कुछ हिसाब मांग सकते हैं। उसमें भी * हुआ। वेंटिलेटर की जो कीमत तय की गई थी, उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि COVID situation को डील करने में पूरे तरीके से mismanagement रहा है। आप वैक्सीन का काफी श्रेय ले रहे हैं, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। जिसको वैक्सीन लगवानी हो, वह लगवाए। आपने 35 हजार करोड़ का प्रावधान वैक्सीन के लिए रखा है। आप यह कितने लोगों को लगा पाएंगे? साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसकी जो clearance मिली है, that is only for 'restricted use in emergency'. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यह स्वास्थ्य मंत्री जी बताएंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछला सत्र राज्य सभा के संसदीय इतिहास में * माना जाना चाहिए। आप किसान, मज़दूर और सहकारिता आंदोलन के खिलाफ जो Ordinance लाए, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी पहली बार प्रधान मंत्री बने। वे सबसे पहला ordinance कौन सा लाए - Land Acquisition Act को समाप्त किया जाए। यह तो भला हो उस समय के समझदार लोगों का, क्योंकि आज तो केवल प्रशंसक लोग रह गए हैं, जिन्होंने उनको बाध्य किया कि आप Ordinance को समाप्त या lapse होने दीजिए। आप ये तीन एग्रीकल्चर कानून लाए, जो कि किसान विरोधी हैं। अभी सिंधिया जी हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री जी के हवाले से कह रहे थे। आप उनका स्टेटमेंट, उनका जवाब देख लीजिए और प्रफुल्ल पटेल जी बोलेंगे, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं उसके गुण-दोषों की तरफ नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। अगर चर्चा होती तो उसके कौन-कौन से ऐक्ट में क्या-क्या कमी है, यह मैं आपको बताता। आपने Congress manifesto की बात की है...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): माननीय दिग्विजय जी, 15 मिनट हो गए हैं।

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I will take five minutes more.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay. Please.

श्री दिग्विजय सिंह : Manifesto में यह कहा था कि इस पर आम सहमति ली जाएगी। हमने मांग की थी आप Ordinance को वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर सदस्यों ने amendments दिए थे। मुझे इस बात का दुख है, मैं उपसभापति महोदय का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपनी सीट पर था और मैंने अपनी सीट से डिविज़न मांगा, लेकिन डिविज़न नहीं दिया गया। इसके बारे में कौन जिम्मेदार है? आज यदि किसान घर-बार छोड़कर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, तो आप कहते हैं कि यह तो षड्यंत्र है, यह कांग्रेस करा रही है। श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय प्रकाश सिंह बादल जी ने प्रधान मंत्री जी को जो पत्र लिखा है, उसको पटल पर रखना चाहता हूं। अकाली दल NDA का सबसे पुराना ally partner है, शिव सेना भी उनसे अलग हो गई। ये सब लोग * आज परेशान हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे तरीके से यह किसान विरोधी है। हम लोग अभी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, जो trade unions के बारे में, मजदूरों के हक में 44 कानूनों को खत्म करके उन्होंने चार labour codes बनाए हैं, उन पर चर्चा नहीं हो रही है, कोई trade unions से चर्चा नहीं कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने भी उसका विरोध किया है। किसान विरोधी कानून का भारतीय किसान संघ भी विरोध कर रहा है, भारतीय मजदूर संघ भी उसका विरोध कर रहा है। लगता है कि मोदी जी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहते हैं। * मैं नहीं जानता हूं। लेकिन साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहकारिता का आंदोलन भी समाप्त करने का, बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट का प्रोविज़न आप देखेंगे, वह भी Ordinance आया है, जिसमें अब cooperative विभाग के शेयर्स शेयर बाज़ार में listed होंगे। इसका मतलब यह है कि कोई भी बड़ा आदमी cooperative sector के किसी भी बैंक, फैडरेशन में शेयर खरीद सकता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सहकरिता आंदोलन के भीष्म पितामह सरदार वल्लभभाई पटेल की आपने 600 फीट की मूर्ति तो बना दी, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, उनकी सहकारी आंदोलन की जो सोच थी, जिसके माध्यम से किसानों की प्रोसेसिंग को involve करके आज अमूल हमारा एक ऐसा institution है, जिसमें किसान को लगभग 70 प्रतिशत उसकी वैल्यू मिल जाती है, आज उनकी आत्मा को आपने खेद पहुंचाया है। आपने मूर्ति बना दी, लेकिन उनकी जो सोच थी, उनका जो विचार था, किसानों की जो आत्मा थी, उसको आपने खंडित किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज हमारा भाजपा से विचारधारा का विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विरोध कोई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से * इस मामले में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी किसानों से चर्चा करने के लिए उन्होंने...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, two minutes more; two minutes more. यह ठीक है कि उन्होंने कृषि मंत्री जी को लगाया, साथ में पीयूष गोयल जी को रखा। पीयूष गोयल जी का किसानों से कोई लेना-देना है क्या ? अगर उसमें किसी को रखना था, तो राजनाथ सिंह जी को रखना चाहिए था। राजनाथ सिंह जी हमेशा पूरे किसान आंदोलन के पक्ष में रहते थे। मैंने उनके दो वीडियोज़ देखे हैं। उन्होंने राकेश टिकैत के साथ इस भावना से बात की थी कि चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, हम किसान के साथ हैं, हम किसान का साथ देंगे। इस प्रकार से उन्होंने पूरे तरीके से किसानों का साथ देने का वायदा किया। पंजाब में केसरिया पगड़ी पहनकर उन्होंने वायदा किया था कि हम किसानों का साथ देंगे। राजनाथ सिंह जी का उपयोग आपने समझौता करने में क्यों नहीं किया? पीयूष गोयल जी किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे!

आखिर में, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के खिलाफ, मज़दूरों के खिलाफ, civil right activists के खिलाफ sedition के cases लगाए जा रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ cases लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात कही थी - मैंने कल उनकी बात को क्वोट किया था, यदि किसी भी लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं को देशद्रोह और राजद्रोह के रूप में देखा जाता है, तो फिर तानाशाही की शुरुआत होती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, यहां पर हमारे रवि शंकर प्रसाद जी बैठे हैं, गहलोत जी बैठे हैं, आप लोगों को बहुमत मिला है हम उसका मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज देश में पूरे तरीके से लोगों को dissent - आज लोकतंत्र में तो dissent is the essence of democracy. उसमें लोगों को जेल भेजा जा रहा है। भीमा कोरेगांव केस में सुधा भारद्वाज, जो कि पूरे तरीके से यू.एस. में, हार्वर्ड में प्रोफेसर थीं, वे तीन साल से जेल में बंद हैं, अनेक civil rights activists जेल में बंद हैं, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। आखिर उनका ऐसा क्या दोष था? इतना ही तो था कि उन्होंने भीमा कोरेगांव के अंदर उनका पक्ष लिया, जो वंचित थे, दलित थे। मैं इसी के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी हालत में हम इस धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, Shri Derek O'Brien was supposed to speak now but since the hon. former Prime Minister, Shri Devegowda, has requested, Derekji is happy to give him his slot. May I now request hon. Member, Shri Devegowdaji, to speak for a few minutes on this topic? आप बैठकर बोल सकते हैं। You can sit and speak.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Sir, today, I have been permitted to speak for a few minutes on the President's Address. I don't want to take much time. There are several subjects mentioned in the President's Address. Sir, being a farmer, I had dealt with the farmers' subjects on several occasions. The contention is now about the three Bills that have been enacted by the House though, on that day, no proper proceedings were able to be conducted as the House was not in order. Sir, today,

more than 90 per cent of the farmers are small and marginal farmers. They have holdings of just half-an-acre or one acre. Now, these Bills have been enacted to protect their interests and it is the Government's impression that this would solve their problems. In my humble opinion, it may be very difficult to solve the problems of the small and marginal farmers. Almost all the previous Governments have tried to see to it that the farmers' condition is improved, but the net result is that while the urban areas are improving, farmers are suffering and they are migrating to the cities. When we were in office, in a coalition Government, the situation as we understood at that time was that farmers were in a really poor condition and so, we took certain decisions to help them. One of the decisions which we had taken under the coalition Government, where I had been asked to perform as the Prime Minister, was to give 50 per cent subsidy on tractors and about 30 to 50 per cent subsidy on power tillers and farm equipments needed for drip, sprinkler and micro irrigation, etc. I think Punjab benefitted the most at that time. We took such decisions at that time to help the poor farmers. Even the classification of poor was not done by any presumption or assumption; the Lakhdawala Committee took a decision on that at that time. I think Madam Gandhi had appointed that Committee, which reported that nearly 36 per cent of the people lived Below the Poverty Line. To help the poor it was decided to give them 10 kg. of rice, 5 kg. of wheat, one litre of kerosene oil and one kg. of sugar. We had taken that decision and at that time, how to meet that expenditure was a major issue. An amount of nearly Rs. 8,900 crore was the expenditure for this particular purpose. I do not wish to deal with all those things. Now, having looked at the farmers' problems, the present Government and the Prime Minister of this country, in their seven years in office, have taken several decisions to help the farmers. There are many issues that I can quote, but I am not going to dispute the programmes that have been announced and implemented since 2014. They have got some results. Only one point I would like to tell this august House. The farmers are not so much agitated. What does the Government want to do with the MSP through the Bill? They think that they are going to avoid middle-men. In my humble opinion, it is not so easy to avoid the middle-men by implementing these three Bills. When the issue started with the farmers of Punjab and Haryana, the Agriculture Minister really took the interest to call them and tried to persuade them. They have met eleven times. He made a promise and told them that whatever amendments they wanted to suggest they could suggest and he would improve and try to see to it that their problem is solved. A categorical assurance was given to farmers' delegation, but their demand to repeal the Bills must be withdrawn. That is the condition on which the entire struggle is going on. Now the hon. Prime Minister, of course, through the mouth of

hon. President of India, has stated "The Apex Court has stayed the implementation of these laws. My Government respects the decision of the Apex Court and shall abide by it." Sir, the Apex Court has stayed them, but has not asked the Government to repeal them. The implementation has been stayed. What next? Now the agitation is going on. There are certain miscreants and certain anti-social elements who have brought bad name on 26th January, the Republic Day. We are all very much unhappy about the incident that happened on that day. Every political party condemned it. Those miscreants must be punished. They have shown disrespect to the National Flag. Everybody is against this; there is no dispute on this. What is the thing farmers are fighting for? The struggle is still going on. The Government has taken the decision to put concrete walls on the other side. But that is not going to solve the problem. There must be congenial atmosphere to see that the whole matter is ended peacefully. That is my concern. I know that the Police have taken every action not to go for firing. They are very much restrained. There is no question of fighting from this side or that side. Our concern is about the farmers and the matter should be ended peacefully. Let them call the farmers' delegation. If need be, some of the leaders from this House also can join or you can also give our suggestions to close this matter. Things are not going to run smoothly if the Government think that they are going to solve this matter by taking all these steps to punish them. They are not, at all, responsible for that incident; the farmers are not responsible for that incident.

11.00 A.M.

Those were some miscreants, some anti-social elements. For that, the farmers should not be punished. It is a State subject. It is in the Concurrent List also. When these three Bills were brought, the opinion of the State Governments should also have been taken into account at that time. That is one thing. I have only a few points. I don't want to take more time. I can understand your feelings.

Now, I would like to talk about river linking. In Karnataka, there is this Cauvery basin issue, the deficit basin. The concerned Minister in the Government has recently announced 90:10 funding pattern for Ken-Betwa Interlinking Project. That is going to help Gujarat and Maharashtra. During Shri Vajpayee's period, it was taken up, but I think first, when Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister, Shri K.L. Rao was the Aviation Minister from Andhra. He was the person who initiated the linking of rivers Mahanadi and Cauvery through Krishna river. So, that was the earlier stage. Now, when Modiji is the Prime Minister, they have taken the first step. Now, I only request,

as Cauvery basin is deficit in the State, and Cauvery River itself is in deficit, States like Tamil Nadu, Karnataka and Kerala have disputes. That matter was almost concluded by the Tribunal but a notification has still not been issued. That is the position. So, I only request the hon. Prime Minister that the preference should also be given to Cauvery and Mahanadi interlinking.

In Karnataka, the HAL is one of the important public sector undertakings. Now, we must congratulate this Government because award for about 83 indigenous fighter aircraft has been given to HAL. It will cost about Rs.48,000 crore. So, that is one of the major shifts taken by the Government of India. We must welcome this.

Now, talking about the urban and rural areas, people are coming from rural areas to the urban areas. From the so-called agricultural sector, why are they migrating to the urban areas? They are not going to get any jobs there also. Slums are increasing, but there is no proper source of livelihood in the rural areas also. That is the reason that they are migrating to the towns. Now, how many slums are there and what is their condition? I am not going to say that only this Government is responsible. Dr. Manmohan Singh also took several steps. But the problem is that the situation is very bad in the rural areas. Normally, we say that about 75-80 per cent of the workforce is engaged in the agricultural sector. But, that has come down to 50 per cent. This is my humble opinion. I do not have any statistics in my hand, but that is the real fact. Now, we have to take further steps to improve the condition. What type of help are we giving to the slum dwellers? We have given them water and light, and they are living in the same house, where they were living about 30 or 40 years back, in the same condition. Their living condition has to be improved. Now, the urban and rural disparity or gap is so much that with whatever steps we take, it is not so easy to bridge this gap. This Government has also announced so many programmes but the only thing is that this will go on. Seventy five years have passed after Independence but the housing problem has not been completely solved. Drinking water is one of the major issues because the groundwater level has gone down. In the previous regimes, we used to take groundwater and supply to all the villages. Now, the groundwater has gone down, we have to search for water from the dams, lift it and give it to people to solve the drinking water problem. This is the major issue. In Karnataka, we have six or seven districts, I am not going to name the districts, where there is so much problem of drinking water. They are struggling very much. For solving this problem, the Central Government must fund the projects which are proposed by the State Government. With these words, I would like to

conclude. I could read your mind; you have cautioned me two, three times. I am so happy that my colleagues have given some time. I do not want to further encroach upon the time of my friends on both sides. With these words, I would like to conclude. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, hon. Member, Shri Derek O'Brien to speak in Bengali.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I will speak in English; little Bengali also.

Sir, in these times, we must be thankful for small freedoms like the freedom to speak without the mike being muted, like the freedom to speak without the video feed being censored, like the freedom to speak and express ourselves in this Council of States as per the rules without being dragged out by marshalls. Yes, Sir, these are small freedoms but in these times, we must cherish these freedoms. Sir, the Members of Parliament, all of them except twelve here, have been sent to this Rajya Sabha by at least 25, 30, 40 or 50 MLAs. Sir, the MLAs who are directly elected in their States have sent us here. So, Sir, if we are feeling the pursuit, the intimidation, the hounding, what our journalists feel, what our farmers feel? This is not about the MPs, this is not about journalists, this is not only about farmers; this is about the Indian citizen.

Sir, on behalf of the All India Trinamool Congress, whenever we have spoken on the President's Address in the last 22 years, we have never moved and voted on a motion against the President's Address. We may completely disagree with it but the *parampara* of our founder Chairperson is stand up, oppose and give your views as we believe that the President in some way is actually presenting what the Council of Ministers have put together or what the Prime Minister has put together. I have got no quibble on that but today we will speak on what was not there in the President's Address or what could have been there. Sir, because this Government has failed India, now, that is not rhetoric, this Government has failed India at many levels. In the time I have in hand, I may touch about ten or eleven levels at which this Government has failed India. Sir, it has failed to uphold the sanctity of Parliament. What happened to the rules and the great traditions here on 20th September, 2020! A lot of young people have been asking me in the last four months what exactly happened, what the rule is. So, I think, a lot of young India needs to understand what exactly the rule was, what happened. I am not passing any judgement on the Chair. I am just

recounting the events. Here is how it works. When the Government brings a Bill, before that, any Member can bring a resolution. Multiple Members brought resolutions. You can't just suddenly decide, two-three hours before. You have to give these resolutions one or two days in advance. The resolution said that these three Bills should go to a Select Committee. Now, this is interesting, because who will be the Chairman of that Select Committee? Why is a Select Committee put together in the first place? A Select Committee is put together so that you can further examine the Bill. Now, who will be the Chairman of the Select Committee? It is from the Government, in this case, the BJP. Who will have the majority in that Select Committee of 30 Members? The Government. Why? Because they have the majority in the Lok Sabha. Those numbers and the Rajya Sabha numbers are reflected in the Committee. So, there also you will have the numbers. And the third thing is: Who will sign off on the final Report? Here again, the Government. All the Opposition was asking for is -- and multiple parties were asking, 16-17 parties, doesn't matter who gave the resolution -- please send this Bill to a Select Committee. The Select Committee can have a discussion with everyone on board. It may take three months or four months. No; and this Government failed the sanctity of Parliament because of its arrogance. These were the rules in Parliament. Rule 252 is very simple. It is not that somebody just puts up his hand and says, "I want a vote". No, no. It is decided before because the notice is given before. I don't want to get technical. But this is the reality which needs to be known. So, what did the Opposition do? Seven Members of the Opposition, believing in this cause for farmers, were suspended. How did we register our protest? To my knowledge, for the first time since independence, seven MPs spent one night by the Gandhi's statue. And our friends and relatives said, "You did a good job." No. It is small, a drop in the ocean. That September 20th was a drop in the ocean, Sir. I am hearing a lot of people say 'the Opposition is not strong, the Opposition is not united.' That is why I said, after a drop in the ocean, look what the farmers have done. It is their movement. It is not anybody in the Opposition movement. Look what they have done. And today, the All India Trinamool Congress feels that yes, we must participate in this Address. But how, in our small way, can we bow our heads to these 194 farmers who passed away? Sometimes, Sir, words are not enough. So, what we thought, me and my colleagues in the Trinamool Congress who are here, I can only tell you what they will do, Shri Sukhendu Sekhar Ray, Shri Dinesh Trivedi, Shri Nadimul Haq and all our Rajya Sabha MPs. I will cut short my speech now for one minute and the four of us will stand in silence in tribute to the farmers who lost their lives. I will continue after that.

SOME HON. MEMBERS: We will also do it.

SHRI DEREK O'BRIEN: I cannot speak for everybody. I can only speak for Trinamool Congress. Sir, when it comes to farmers, I represent a lady who knows a few things about farmers. This is a well- documented modern Indian history. A 26-day hunger strike, not in Singhu but in Singur, is documented modern Indian history. So I wasn't surprised when a few days into the farmers' agitation -- it was December the 4th -- Ms. Mamata Banerjee said, 'Please go there with the MPs. Make sure there is no party flag, no symbol, and avoid television cameras. Just go there and listen to the farmers.' And we went. Again, on December 23rd we went and listened to Harbhagwan Singh, Rajpal Singh from Hoshiarpur, Harvir Singh from Amritsar, Gurpal Singh from Hoshiarpur and at least 25-30 others who we met separately from Tarn Taran Sahib. We heard their stories. They didn't know about some parliamentary rules. But they were expressing themselves. And what were we doing? We were listening.

Sir, 26th January. I think the whole House agreed on what we all feel. But just imagine if that tractor incident, that unfortunate tractor incident where a farmer died under 'mysterious circumstances', just imagine if that had happened in Bengal or Maharashtra...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, one minute.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*... I am not yielding. ...*(Interruptions)*... Let me finish this. ...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please continue.

SHRI DEREK O'BRIEN: This is the issue. Let me finish my point. Imagine if that had happened in Maharashtra or in Bengal, and who is in charge of law and order there? All I am saying is that the truth be told. I am not coming to any conclusions. Let the

truth come out. Who is in charge of that? The Home Minister of India is in charge of it. Do a proper inquiry and let the truth come out. What more am I saying? ...*(Interruptions)*... What more am I saying? ...*(Interruptions)*... Political and administrative responsibility is with the Prime Minister and with the Home Minister. Let us be very clear about this.

Now we come to farmers. Now they are saying 18 months. How's this done? Because there is no Mr. Arun Jaitley to spend half- an-hour to try and understand and explain. This Government is very clear. It's our position and I am sure it's everybody's position -- the repealing bill, 2021. That will repeal all those three farmers' Bills. Because you have asked for 18 months in any case. In all humility, we have taken the liberty of drafting the repealing bills, and I will share it with them. You repeal these three Bills. There is a way to do it. Follow the system and do it. You will put it on pause for 18 months. How? This is the way to do it.

Sir, when it comes to farmers, you have to see which party I am speaking from. I am speaking from the All India Trinamool Congress. The Prime Minister of India said that by 2022 farmer income will be doubled. That is the promise. At current rates, if that were to happen, it will not happen before 2028. पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ? तृणमूल गवर्नमेंट में क्या हुआ? From 2011 to now, not double, the farmer income has been tripled in West Bengal.

Sir, let's talk more about farmers, because sometimes the arrogance, the hubris is not letting the Government listen. So, take some examples. Rs.5,000 per acre is Krishak Bandhu Scheme in Bengal; Kisan scheme by the Prime Minister is Rs.1,200 per acre. Then, there is crop insurance scheme, Bangla Shasya Bima. Who pays the premium for the farmers? The farmers do not pay; the State Government pays. In the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the farmers have to pay premium. I am glad that one-and-a-half years ago when I spoke on the subject, the Agriculture Minister was here and he acknowledged this. That is why, I am saying this with a lot of pride; for agricultural farmers, over the last five years, it was not that any political party gave it, the Government of India gave the award to Bengal. If you are talking about farmers, let us talk about how this Government views farmers across different States. I am very happy that the Government acquires, on behalf of FCI, from different States. It does not matter from which State; the more you acquire, the better. Now, let us go with paddy. In Uttar Pradesh, 71 lakh metric tonnes. It is good. I am happy for Uttar Pradesh; in Haryana, 64 lakh metric tonnes; in Telangana -- I am

happier -- 111 lakh metric tonnes; in Bengal -- we know how much they love Bengal -- not lakhs, for the largest rice producer under the Central Government schemes, it is 76,000 metric tonnes. These are the numbers I am giving you on the floor of Parliament. Dispute them.

Sir, this Government has failed in Covid preparation. I said preparation. We all know about the visit. Today, we are getting touchy about other persons commenting on the things which are happening in India. Who said this line before the Trump campaign? "अबकी बार ट्रम्प सरकार" किसने बोला था? उद्धव ठाकरे जी ने बोला था? ममता बनर्जी जी ने बोला था? हेमंत सोरेन जी ने बोला था? They are talking about interference. I am on preparation of Covid. On 11th of March, Covid was declared. WHO declared a pandemic. We were all here in Parliament. Where is my senior colleague, Dinesh*da*? He was here. He told me that day. He is much senior to me. He said, पार्लियामेंट चलेगी, I said, क्या बोल रहे हो? He said, हाँ, मध्य प्रदेश, तब! That is the second failure in the preparation. The third failure of the preparation was 24th of March, which we all know. Just four hours! Then, it is very interesting. And I am willing to say that this part was well done. The Centre, after bulldoze and bulldoze, figured out that the States are the implementing authority. Today, as much as BJP wants to take credit for all this, the States are the implementing authority. After the hotspots were identified in March, things got better. One Chief Minister wrote to all Chief Ministers mentioning about trains and migrant workers. Check that letter. It was of 26th of March by the Chief Minister of Bengal. Isolation wards were set up in Covid preparation. Now, what are you doing? This is actually what we love about this Government. When it comes to taking the credit, the Centre will take the credit. And when it comes to passing the buck, it passes the buck. This is the Council of States. I would appeal to all the Members to find out how much was given to their States for Covid. I have got the numbers for Bengal. Bengal has spent Rs.4,000 crore on Covid. It needed Rs.11,387 crore. Here is another number for you in Parliament. It is Rs.279 crores. Now, you want to come and win Bengal. Maybe, some of the next speakers from the BJP would answer these questions. Maybe, the Prime Minister would answer these questions. Maybe, the Home Minister would answer these questions because so far we had two newbies, with all respects, who have spoken for BJP and it is their prerogative, they can have anybody to speak. You know, Sir, there are two types of girls or boys in the class. One who can come first in class and the other one who can also do well but he can copy and come first but can never come first in class. While I am on the subject of health; 'Ayushman Bharat, Ayushman Bharat!', very good. Ayushman Bharat started in 2018 by the hon. Prime Minister. Bengal

Swasthya Sathi started two years earlier by the hon. Chief Minister of Bengal. That is one difference. It was two years before you.

Secondly, the cards that are in Bengal are issued in the name of whom; of the woman in the family. It is empowering women.

Both are five lakhs. In the State's case, the State pays 100 per cent and the Centre pays 40 per cent. The State also has the humility -- we also want to see some humility from the Central Government -- to say three months or four months ago that: 'Hey listen, not all of you may have got your cards. So, here is a new scheme, door to door scheme, Duare Sarkar.' We have not done everything in the last five years. We are not perfect but we will, we can. Sir, two crore sixty lakh people have registered and are now getting their cards. Not arrogance, Sir, humility.

Fourthly, this Government has failed the migrant workers. During the lockdown, all of us had a good chance to do a lot of reading. I read one of the best books on migrant workers. It is from Gujarat, from Ahmedabad. The gentleman is a Professor of IIM, Ahmedabad. His name is Chinmay Tumbe. There, he says: 'Out of every six households in India, they have one migrant worker.' It is a fabulous book. Ten crore migrant workers account for 10 per cent of India's GDP. A lot of good work comes out of professors in Ahmedabad. But what did you do here? Four hours, no trains! What did you do last week in Bengal? What did you do? In four hours, chartered plane. Now, let me explain the significance of this because this fact may be lost by so many of you. The hon. Home Minister was supposed to come to Bengal for a rally. It is a political rally. He needed to stay back in Delhi, good reason. So, what was done? Two-and-a-half or one-and-a-half MLAs, who were switching sides, were sent the chartered plane and brought there in four hours. I wish so much love, affection and care was shown for some of these migrant workers and we have seen those pictures. When it comes to migrant workers and when we ask for data in Lok Sabha and Rajya Sabha, then, this Government truly becomes the NDA - 'No Data Available'. You ask them, they would tell you in Parliament, 'No Data Available.'

Fifth one, this Government has failed India's federal structure which is enshrined in the Constitution. I can give you 20 examples but I would give you only two or three. Let us talk about cess. Young people of India need to know 'cess'. Tax, when collected by the States, there is a devolution given to the Centre, 40 per cent goes back to the State. That is the devolution, sharing. What about cess, when

Government imposes cess that is not shared with the States? Hon. Vice-Chairman, Sir, this would interest you even more because you are from my neighbouring State, Odisha. Sir, so, the cess is never given, never shared with the States. This time also you had a cess. It is very interesting that out of all the gross revenue -- because the *Rashtrapatiji* had mentioned in his Speech about federalism -- in 1980, two per cent was cess. Now, what is the cess? Now, cess is, almost 16 per cent is being collected as cess. Every State Government must be aware of this that it is from two per cent to 16 per cent as cess. Every time you collect a cess, you deprive the States. These days nobody talks about the price of brent crude which is now down to Rs. 20-22 and you get that tailwind of the Government. But, my colleague is speaking on the Budget and he will give you more on that. The devolution is also interesting. There is 42 per cent of devolution and where is the hocus-pocus happening here? It is on the decrease funding pattern of Central Schemes. First it was 60 per cent Centre, 40 per cent State or 50 per cent Centre, 50 per cent State. Now, you see the schemes. It is no more, look carefully. It is 75 per cent State, 25 per cent Centre. This is an assault on federalism. This Government has failed federalism and it, actually, saddens me because, today, the Home Minister was the Home Minister of a State and the Prime Minister was the Chief Minister of a State. So, these are actually children of the federal structure. Now, Sir, about the MPLADS Funds. The Prime Minister will be here. I can't put a tube well up now. Yes, Rs. 8,000/- crores were needed. They have to find a way to allow the MPs, Lok Sabha and Rajya Sabha, to that freedom, a small freedom, of five crores of rupees. Again, there is an assault on federalism. It is all hocus-pocus. There is no Railway Budget. I used to love speaking on the Railway Budget. Now, listen to the Railway as to how they have failed federalism. Till 2015, every Railway project was 100 per cent done by the Centre. Post this new, in the last few years, now, what has happened is there is a new mechanism in place called the SPV, Special Purpose Vehicle. What's the deal there? The State has to pay 50 per cent and the Railways have to pay 50 per cent. Why? Then, you will say that you do not do politics. There is a Pink Book of the Railways which still has not been tabled. I hope they table it today which gives you the State expenditure. Last year, you shelved 31 projects of Bengal, all started by Ms. Mamata Banerjee. Now, suddenly, it is winter or may be some other reason, I do not know, you suddenly said that you are giving Bengal some more money this year. अप्रैल-मई महीने में क्या हो रहा है? Look at the total which was supposed to be given to a State and how much of that has been given? Now, Sir, about the infrastructure. Look at the Budget papers. It is Rs. 1 lakh crore on infrastructure, that is it. Now, you come and announce pre-election. They announced 675

kilometres of roads. You see that number one in infrastructure roads is Bengal. Sir, 89,000 kilometres of roads. I am only giving you Bengal examples. I am sure that Kerala will have examples and Maharashtra will have examples. It is because someone said why were we not in the President's Address? These are the issues which the President could not address. We understand that. We have full respect for that. Why? It is because this is the way it is done. You have failed India's youth. I do not want to repeat some of the points because Digvijaya*ji* had the same points, and I am happy to acknowledge that he has covered this really well with jobs for youth. One crore jobs were lost in India. Some said that it is one-and-a half crores. Bengal reduced unemployment by 40 per cent during the pandemic. These are not the Trinamool Congress' figures and not the Bengal Government's figures but these are the Government of India's figures. What about MGNREGA? Sometimes we have to remind them. "गड्ढे खोदने की स्कीम" यह कौन बोला था, किसने बोला? The former Chief Minister of Gujarat said this on the 27th February, 2015. By the way, I don't mean to keep talking about Bengal, but what can I do, Bengal is number one in MGNREGA; I am happy, I want to say it. Now what has happened, and this is about MGNREGA. There are still issues of late payment of wages, there are still insufficient budget allocation, still low wages, but now MGNREGA: Good! This Government has failed India's women. This Government has failed India's children. Not empty rhetoric. National neonatal mortality rate, the national average is 22; Gujarat, 21; Bengal, 15.5 . The lower the figure, the better. Infant mortality rate; 28 is the national average; 31, Gujarat; 22, Bengal. Under five mortality rate; national average, 34; Gujarat, 37; Bengal, 25. Don't sell us this fake Gujarat model. You can go through all parameters. It is a total, fake Gujarat model. Textbook distribution; number one, Bengal, 99.7 per cent; Maharashtra, 81 per cent. Now, about women. This is not flowery stuff which will make the 9 o'clock headlines, but these are the hard numbers which this country needs to know. I am not speaking in Bengali today. Why? Most people in Bengal already know these numbers. That is why it will happen again in April and May. Three, increase in crime against women. Made on the floor of Parliament, the national average is 20 per cent and these are 2018-19 figures. Bihar, plus 21 per cent; Rajasthan, plus 33 per cent--this is about crime against women--UP, plus 56 per cent; Haryana, plus 64 per cent. Who is ruling these States? Under the only woman Chief Minister in India, in her State, not plus, it is minus21 per cent; it is Bengal, Mamata Banerjee and the people of Bengal.

Sir, I will now speak on one more subject close to your heart, the Women's Reservation Bill. The Prime Minister is coming on Monday. Bring the Women's

Reservation Bill. Don't table it in Lok Sabha because again it will get lapsed; bring it. Trinamool Congress doesn't need the Women's Reservation Bill. Guess why? World average in Parliaments for MPs is 25 per cent. It is world average, international average. National average is 13 per cent. BJP has about 10 or 11 per cent. By the way, this is not for giving tickets to women. This is of elected women MPs. In Trinamool Congress, close to 40 per cent MPs are elected, 41 per cent in Lok Sabha and 31 per cent in Rajya Sabha. Big-big *bhashan*, some catchy phrase! As we say,

*"First, take care of Delhi And then think of Bengal.'
May I say it again? 'First, take care of Delhi
And then think of Bengal.'"

Everything I say in Bengali does not need to be translated. Ram Gopal*ji*, I think I will make it nicely in English and then tell you because the Bengali is too good. It basically means, first take care of Delhi, then think about Bengal. This Government has failed the economy even before the pandemic. Don't make the pandemic the excuse. You forgot, who got up and said, -- my Hindi is not good, nor can I read from a teleprompter; so, I will just paraphrase it -- "Give me 50 days and then do, whatever you want, to me". And, what did she say within two hours of the demonetisation announcement? It is on record. "Withdraw this draconian decision", she, in her *chappals,* said this. Demonetisation failed every single objective, every single one, that of black money, demonetising currency. I have a lovely figure here. Fake currency - 9 crores; all States caught fake currency. And, we keep saying, 'Gujarat is never number one'. In this, Gujarat was number one. And, I have a lot of friends in Gujarat because Dinesh*da* makes the best dhokla; they are also from Gujarat. So, we have a lot of respect, love and respect for the people of Gujarat. But, this is the reality. Some newbie came and told us about Jammu and Kashmir. I wish him well. After demonetisation, terrorism was supposed to stop. These are the numbers of Government of India - 2016, 322; 2017, 342 and 2018, 614. What did you tell us? And, it is interesting. I remember that. Just after that, Mamata*di* came to Delhi and she said, 'we will walk to Rashtrapati Bhavan, go and submit a memorandum'. And, I am saying this with all respects to all the Opposition Parties here. Then, I told her that some of us are telling us, *Didi,* nobody is walking with us, only two parties have agreed. Which are the two? We said, 'Omar Abdullah*ji* is coming down from Kashmir; so the National Conference and the Shiv Sena'. So, that

* English translation of the original speech delivered in Bangla.

was the combination which walked from here to Rashtrapati Bhavan on demonetisation. And after that, everyone in the Opposition joined. This is not about one-upmanship. But, this is what it is.

Number nine, this Government has failed to protect and safeguard the legacy of India's jewels. I will breakaway now. This is the 100th Year of Satyajit Ray. Based on a story of Munshi Premchand, he made a fabulous film, his first film in Hindi, *'Shatranj ke Khiladi'*. Have you seen it, Sir? But, you do watch it; I don't know whether it is on Netflix. But, you must watch it. There is a story of two noble men. Two of the noble characters are completely engrossed in a game of chess while their entire State is in ruin. People are angry. People are upset. People are committing suicide. But, they are engrossed in this game of chess. Sir, I may be a little biased because I am from Bengal. So many people believe -- in fact, I think this film was made in the 70s -- that Satyajit Ray was the visionary. He was the visionary because a lot of buying and selling is happening. The 23 PSUs are being sold. In fact, 28 PSUs are being sold. We are selling the nation's gems. But, the buying and the selling is happening. Everywhere, we are seeing it, MPs, MLAs. These public sector undertakings are about what, Sir? Job creation, social welfare, overall economic growth; you are selling the family jewels. The limit has been increased from 49 per cent to 74 per cent in FDI insurance. Sometimes I do not get too surprised, when two people who spoke from that side were once this side. They have now gone to that side. All India Trinamool Congress has opposed 74 per cent in FDI insurance from day one, Sir, we have opposed it from day one. But, then often it becomes; the stand you take depends on where you sit. The same goes with GST, look at the track record of GST as the Chief Minister of Gujarat. We are all for GST and we warned you that do not rush the implementation of GST. Sir, what have we done so far? We have done so far; they have failed to uphold the sanctity of Parliament, they failed India's farmers, they failed India's Covid preparation, they failed to strengthen the federal structure, they failed India's youth, they failed India's women, they failed India's jobs, they failed India's economy, they failed to protect the legacy of the jewels. They have also failed the Indian media. Here, I want to salute the frontline workers, the young boys and girls who are reporters, who do not belong to any big corporate media house, who are still fighting their battles. You can intimidate or threaten the media barons; you cannot intimidate and threaten these young boys and girls, and from Parliament, we want to tell you, we will do all it takes, in all humility, to be with you in these difficult times. Then, BARC is another story. How are the ratings? Time today is short, but that is another story. Who is telling what, how, where, and when it comes

to all this, we keep having debates. There are fake news, who do you blame for fake news? The IT Cell of BJP party; no. Why are you blaming all the wrong people, blame the person who is responsible for it. Sir, please listen to this. In the year 2018, it is the translation, it was said in Hindi, I have got the video. In the year 2018, I am saying this in English, "we are capable of delivering any message we want to the public whether sweet or sour, true or fake, we can do this because we have 32 lakh people in our WhatsApp groups; Akhilesh Yadav slapped Mulayam*ji*, यह तो फेक न्यूज़ है, no problem" who said this? This is no IT troll. I was hoping that he be here because I am with Mamta Di's party, what we say, we will say eye to eye and straight to your face, Amit Shah ji said this at a rally in Rajasthan, सच का झूठ और झूठ का सच। Sir, you have failed different groups of people. I have six minutes to go, Sir. Now, Citizenship Amendment Act, I have got all the footage from here. Sir, 19 lakh Bengali Hindus, I repeat, 19 lakh Bengali Hindus are in detention camps. Now, you are taking one-and-a-half years and promising citizenship to *Matuas* in Bengal, Sir, already they are citizens of India. I tell you why? How can you be an elected MLA if you are not a citizen? How can you be a Minister in Bengal, if you are not a citizen? You are already a citizen. How can you be an elected BJP MP already, if you are not an Indian citizen? Who are you trying to fool? You failed the citizens.

In 2018, there was 7 per cent increase in crimes against the Scheduled Castes. In Uttar Pradesh, the increase was 25 per cent. In Bihar, the increase was 14 per cent. In Bengal, on the floor of Parliament, I can tell you it is 0.3 per cent. Crimes against Scheduled Castes, the first one was Castes, this is Tribes-- crime against Scheduled Tribes 26 per cent increase in 2018, Madhya Pradesh 23, per cent, Rajasthan 21 per cent, Bengal 1 per cent. Those were the points, Sir. Now, in conclusion, I must thank the President, Rashtrapatiji, he quoted the elder brother of Rabindranath Tagore, and he quoted it perfectly. The Finance Minister, I must thank her, she quoted Rabindranath Tagore and she quoted it perfectly. I am very happy. It is another matter what the party people from here are going and saying there. They are changing the birthplace of Rabindranath Tagore, they are saying he was born in Santiniketan. ...*(Interruptions)*.. This is not from some small party worker. He was one of the two big boys. You know whom I am referring to. ...*(Interruptions)*.. Then Birsa Munda statue, they go and garland it, then someone said, यह बिरसा मुंडा का statue नहीं है, it is a wrong statue. Netaji, you know, and somebody today was, one of the speakers from Bengal, he is a Nominated MP, and also the other speaker, they are invoking Sardar Patel and they want us to invoke history. If I start invoking history today, as I had a lot of quiz in the past before I became elected Trinamool MP, today

is February the 4th; history, on February the 4th, 1948, Sardar Patel banned the RSS. ...*(Interruptions)*.. This is not unparliamentary. ...*(Interruptions)*.. Now you make a statue, good. So, don't ask us to invoke history because we have a lot of history to invoke. Sir, let us come back to Rabindranath. ...*(Interruptions)*.. In five minutes, I am finishing. Sir, I also have a Rabindranath story from school, if you allow me because I have a lot of heavy data and sharing so little. It is a school story, a lighthearted. So, I was in Class 7, and I took part in a fancy dress contest and the music teacher was one judge and the Bengali teacher was the other judge. There were 44 students in the class and teachers were there, our Bengali teacher and the music teacher and hurrah! I won the fancy dress competition. I went dressed as Rabindranath Tagore. ...*(Interruptions)*.. Wait till I finish my story. I haven't finished my story. Two weeks later, I got my Bengali Literature paper results. The same judge who was there and there she called me, it was the same lady who gave me first, she came and gave me, I looked at the Bengal literature paper, I got 14/50. I said, 'Madam, what happened?' She said, 'That was the fancy dress, this is the real thing.' These school stories are very beautiful stories, make me feel so nostalgic. Don't they, Sir? Tagore had an outlook which was Vishwa Bangla. Means Bengal is global, that was his outlook in many ways yet I have fabulous stuff on humanism, humanity, I am not going there, but on Vishwa Bangla, and that is what the Bengal Government is trying to do in the last ten years because this debate otherwise is ...*(Interruptions)*.. In Bengal, you be Agarwal, you be Sharma, you be Chatterjee, you be D Souza, you come, you come to Bengal, you are working in Bengal, you are living in Bengal, you speak broken Bangla, all is good. You are a part of the global thing but what we mean by outsiders is, don't come as tourist gang three-four months before the ...*(Interruptions)*.. I am finishing. ...*(Interruptions)*.. There are two quotes, Sir. I am going to read a quote in the spirit of Vishwa Bangla by Tagore.

*"You may write me down in history,
With your bitter, twisted lies,
You may tread me in the very dust
But still, like dust, I'll rise."

This is for our farmers. Look at the beauty. The lines are in Bengali. But, they were not written by Rabindra Nath Tagore. That is 'Bengali Global'. These lines are

* English translation of the original speech delivered in Bangla.

written by Maya Angelou, the famous and contemporary American poet. We translated it in Bengali.

Now in English, for our farmers, it reads: You may write me down in history with your bitter twisted lies; You may tread me in the very dust; But still as dust I shall rise.

I want to tell Har Bhagwan Singh, who didn't understand the English translation of Maya Angelou or Bengali. I want to tell the farmers whom I met; Mamata*di* sent me to meet them along with my colleagues from Hoshiarpur, from Amritsar; गुरपाल सिंह जी, सुन रहे हो न? The farmers from Taran Tarn Sahib and to every farmer of the country, यह आपकी रोज़ी-रोटी की बात है, हम सब आपके साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय बंगला।

SHRI N.R. ELANGO (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, It is my maiden speech. Please consider giving me more time. I thank you for the opportunity given to me to address this House. I thank my leader, Thiru M.K. Stalin for having proposed and made me a Member of this House. I thank my party and its leaders for having wholeheartedly seconding the proposal. Belonging to the Dravidian culture...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, for your information, the maiden speech can be done in a subsequent one when you are speaking on a specific Bill. Please finish in six minutes.

SHRI N.R. ELANGO: Sir, I will try to finish within that time. Belonging to the Dravidian culture, I would like to express my gratitude to the leaders who have shaped and influenced the Dravidian ideology-- Dr. C. Natesan, Raja Sir Panagal Ramarayaningnar, Sir P. T. Tyagaraya, Sir A. T Panneerselvam, Sir T.M. Nair, *Thandai* Periyar, *Perarignar* Anna, *Tamilina Thalaivar* Dr. Kalaignar and *Inamaana Perasiriyar* Dr. Anbazhagan. But for those great leaders, people like me would have remained uneducated, leave alone coming to this august House.

Sir, my leader asked me to explain to this great House the plight of Tamils and represent the cause of Tamil Nadu and, for that, just to remphasise what *Arignar* Anna spoke in this House. I recall the words of *Arignar* Anna on the floor of this House on 25th January, 1963. I quote: "Sovereignty does not reside entirely in one particular place. We are having a federal structure. That is why, the framers of the Constitution

wanted a federal structure and not a unitary structure because as many political philosophers have pointed out that India is so vast,--in fact, it is described as a sub-continent--the mental health is so varied, the traditions are so different, the history is so varied, that there can't be any steel frame unitary structure here.

I thank His Excellency, the President, for having informed that there are now 562 medical colleges in our country and 50,000 PG and UG seats are increased in those medical institutions. Because of this increase, there is no need for the all-India quota in the State Government hospitals. So, I request this Government to surrender all the all-India quota seats from the next academic year to the relevant State Governments and colleges.

After seeing the protest of farmers, Sir, and after hearing that 160-190 farmers died, I came with a very fond hope that this Government will withdraw the agricultural laws. But, that was not happening. It is made clear that they are not going to do that. In his Address, the President stated that one lakh crore rupees have been allocated to the Agriculture Infrastructure Fund.

12.00 Noon

It is stated that about 100 Kisan Rails were being introduced, but in the Budget Speech it is stated on page 9, para 47, "Warehousing Assets of CPSEs such as Central Warehousing Corporation and NAFED among others will be monetised." The President's Address speaks about 100 Kisan Rails. The Budget Speech says, "Railways will monetise dedicated freight corridor assets for operation and maintenance after commencement." On the one hand, you are saying that we are spending crores and crores of rupees of the tax payers for the development of the country and on the other hand you are selling all those assets. This is like using the powers for an alien purpose. All the three farm laws which are now introduced and passed are necessarily occupying the field of the State's power. There was no need for the Centre to legislate in such a tearing hurry, exceeding its legislative competency in a matter entrusted exclusively to the State. Further, though the legislations were enacted under the guise of alleged reforms for the farmers, their interests were not even considered. In the State List, Entry Nos. 14, 28, 30, 45, 46, 47 and 48 completely occupy the field of agriculture. The Union Government exceeded its legislative competency and passed those agricultural Bills. This is against federalism. After 30 years of Arignar Anna's speech in this august House, hon. Supreme Court of

India, in S. R. Bommai's case said, "Federalism is the basic structure of our Constitution." That is now being flouted. On 13th September, 1970, our former C.M. of Tamil Nadu, Mutthamizh Arignar Dr. Kalaignar spoke about the importance of State autonomy. He demanded greater powers for the States politically, administratively and fiscally. In 2018, our leader, Mr. M. K. Stalin, wrote a letter to the hon. Prime Minister and ten other hon. Chief Ministers. In that, he was highlighting the State's autonomy. The farm laws are paving way for a cartel formation. It gives a chance to the sponsor to create encumbrance over the crops without the knowledge of the farmers. The sub-divisional authority is given power to decide the dispute between the farmer and the sponsor. There is no clarity. What kind of a procedure is he going to adopt? Whether the procedures of Evidence Act will apply or not is not known.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH) *in the Chair.*]

The Essential Commodities (Amendment) Act, in fact, runs contrary to the main Act and its objectives, and in short, all these laws, are going to create a black-marketing regime. One important question needs to be answered. What kind of a country are we? What kind of a nation are we going to be? Our actions today determine the country of tomorrow and forge the thoughts of leaders of tomorrow. Today we are at the crossroads where we may draw upon our inner strength, and the idea of India we grew up is where there is harmony, love and the resolve not to yield to the forces of destruction. While we do so, it is important to remind ourselves the principles of secularism. All of us should join together to fight hatred and divisive forces. There is an idea of India that our constitutional makers have in their mind. It was one of appreciation of different cultures, religions, languages, not merely of tolerance. It is such a country that I want my children to inherit. Sir, please give me two minutes and I will finish. Sir, of late, we are seeing the hon. Prime Minister and the Ministers quoting Tamil poets. It maybe because of ensuing elections in Tamil Nadu. Anyhow, we thank them. But, one Tirukkural which they forgot to consider is this. We are calling farmers, in Hindi, as *anna datas*. Tirukkural said:

*"Who ploughing eat their food, they truly live:
The rest to others bend subservient, eating what they give."

* English translation of the original speech delivered in Telugu.

It means that those who are ploughing are living and all others are leading a subservient and dependent life on farmer. We are passing Bills which are detrimental to farmers! So, the Government has to consider that.

Sir, numbers play a major role in democracy. It is hence believed that the majority can do whatever it wants. Are they thinking whatever they do is right? I quote another couplet from Tirukkural:

*"Though things diverse from diverse sages' lips we learn,
'is wisdom's part in each the true thing to discern'.

It means, to discern truth in everything whoever spoke is wisdom. So, to know truth and to get ground reality, you have to hear what the opposition says. You may call us 'minority' and hence will not hear our voice. What will happen if you continue with this attitude? The answer by Thiruvalluvar is this:

* "The King with none to censure him, bereft of safeguards all,
Though none his ruin work, shall surely ruined fall"

It means, a king without trenchant counsel will fail on his own.

Therefore, Sir, I request the Government to withdraw the farm laws, surrender all medical seats to the respective State Governments and uphold federalism. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Now, Dr. Banda Prakash. You are left with only two minutes. But, try to conclude as early as possible.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, hon. Chairman gave some time. When we discussed about increasing the time for debate, we requested for that. I have taken a little more time and he is left with less time. So, kindly give him some time.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Thank you respected Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on President's Address.

---

* English translation of the original speech delivered in Telugu.

Sir, hon. President said in his Address that we are proud to develop Corona vaccine indigenously. Hyderabad is a very big vaccine centre. It is also called the vaccine capital of the world. Our units in Hyderabad are manufacturing a maximum of 6 billion doses annually and contributing 1/3rd to the global vaccine production. That is why our hon. Minister, Shri K.T. Rama Rao Garu, has requested the Union Health Minister to set up a vaccine testing and certification laboratory and a Government medical store depot in Hyderabad. The hon. Vice-President of India and Chairman of our House, Shri M. Venkaiah Naidu Garu, also advised the Government of India to consider the request for setting up of a vaccine testing and certification lab in Hyderabad.

Sir, the Government is also insisting upon Atmanirbhar Bharat to further strengthen self-reliance in agriculture. They are also chanting the mantra of 'Per drop more crop', wanted to complete irrigation projects and follow better agricultural practices. I don't want to go into farm laws. Our leader, Dr. Keshava Rao Garu, had already spoken on the subject. Sir, our Telangana Government has undertaken a good initiative in agricultural sector to increase the income of farmers. We are giving 24-hour uninterrupted quality free power to farmers. We have completed our twelve old irrigation projects and twelve re-designed project works are also near completion. We have already spent Rs. 1,17,483 crores on these projects. On Kaleshwaram Project alone, we have spent Rs. 18,119 crores. We have Rythu Bandhu Scheme. We were the first State in the country to start the Rythu Bandhu Scheme. After that, many States and even the Central Government followed the State of Telangana. We are giving twice in a year Rs. 5,000/- per acre for each crop. That means, we are paying Rs. 10,000/- per acre every year to the farmers as a subsidy input. We have also initiated the Rythu Bima Scheme. A total of 32.73 lakh *pattadar* families are enrolled in the Rythu Bima Scheme. It has been linked up with the LIC of India. So, whoever dies -- whatsoever may be the cause, whether accidental death or a natural death -- his next of kin is paid five lakhs rupees within five days. This amount is directly transferred to their accounts. Till today, we have paid Rs. 2,106 crores to the beneficiaries.

For restoring the minor irrigation tanks and lakes in Telangana State, our Government has undertaken the task of rejuvenating the tanks and thereby has stored 265 TMC water across the State during the last five years. The income of farmers have increased by 78.50 per cent.

Apart from that, in the industrial sector also our Government is taking several steps to develop the sector. Particularly, I would like to mention that the Government of Telangana has initiated the TS-iPASS. It has generated more than 14,50,000 employment opportunities in the State. A large number of companies have also been established in Hyderabad.

The hon. President also made a mention about the Mega Textile Parks. Perhaps, Telangana is the first State in India to have initiated the concept of Textile Parks. We have initiated the Kakatiya Textile Park at Warangal over 2,000 acres of land. A budget of Rs. 300 crores has been allotted for State developmental programmes. We request the Government of India to include the Kakatiya Mega Textile Park in the Mega Textile Park Scheme, which has seven mega textile parks.

There has been a tremendous growth in our IT exports. During the year 2019-20, there has been about 8.09 per cent growth which is more than the national average. Our growth rate is more than double of national average at 17.93 per cent. The IT department has released a number of statistics to indicate the growth rate of Telangana IT sector. That's why we have requested a number of times, it was promised by the previous Government, to provide better ITIR Scheme to ensure that the cities, like Hyderabad, continue to witness tremendous growth in the IT sector, which has been witnessed during the last six years. Such schemes provide major boost to the IT sector, as it looks forward towards the Government for economic development. Sir, under Jal Jeevan Mission, the Government proposes to give tap connection to every house. "हर घर को नल का पानी", actually, this was initiated first in Telangana in 2016. The first phase of the Programme was inaugurated by hon. Prime Minister, Narendra Modi*ji*. Now, under Mission Bhagiratha, Telangana has completed almost 98.75 per cent households. They have been provided with tap connections. First, rainwater is taken. It is filtered. It is then monitored by 70 labs in the entire State under the Ministry of Chemistry and Microbology. We have stood first in Mission Bhagiratha. Earlier, NITI Aayog also recommended a sanction of Rs.19,500/- crores for the Mission Bhagiratha Project. But, as on today, we have not received any money. Even for Mission Kakatiya, they have recommended Rs.5,000/- crores, but we have not received any money. We have always been receiving a lot of appreciation from the Centre and other respective Departments, but we are not getting any money for such projects. The entire country is discussing these particular reforms. The reforms initiator in 1991 was Shri P.V. Narasimha Rao. In 1991, Shri P.V. Narasimha Rao, the then Prime Minister, initiated a number of reforms in the country. Even our Telangana Legislative Assembly unanimously resolved to confer

Bharat Ratna on P.V. Narasimha Rao Garu. We also request that the Central University, Hyderabad be renamed as P.V. Narasimha Rao Central University of Hyderabad. We request the Government of India to name a road in New Delhi after Shri P.V. Narasimha Rao.

On education front, the hon. President has said that we should provide quality education to students. The Telangana Government, after the formation of Telangana, has started 281 residential schools for OBC students. About 200 colleges for SC students have been started. Also about 250 colleges for tribal students have been started. About 28 Junior Colleges for tribals have been started. We have also started 22 Degree Colleges. Now, we are having 23 Ekalavya Model Residential Schools. The number of Mini Gurukulums is 29. Earlier, the Government of India sanctioned a National Design Centre for Hyderabad. But, after bifurcation of the State, the Centre went to Vijayawada. Therefore, we request that they should sanction a National Design Centre at Hyderabad also. Another request that we made is for sanctioning of IIIT at Karimnagar. We also request for sanctioning of Indian Institute of Science Education and Research at Telangana. Another request that we make is about establishment of Indian Institute of Management in Telangana State. According to the AP Reorganisation Act, there were so many promises made to Telangana State. Out of that, one is about establishing Tribal University for Telangana. We have given the land and also the minimum facilities. In the last three years, we have requested a number of times, but they are unable to start a tribal university in Telengana. We do not know what the reasons are. They had also promised for a coach factory under the Act, but, as on today, we are waiting for the coach factory. They are making promises to other States, places, wherever there are problems. We have demanded it a number of times, but we have not been given any coach factory.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HUNUMANTHAIAH): Please conclude, Banda Prakashji.

DR. BANDA PRAKASH: I will just conclude. Even they have promised Bayyaram Steel Plant also under the A.P. Reorganization Act. But as on today, they have not fulfilled that also. They are not even fulfilling their promises. We were expecting so many things in the hon. President's Speech. We were expecting OBC Reservation in the Legislature. Our State Legislature has already resolved and sent it to the Government of India for 33 per cent reservation for OBC, even for women reservation in the Assembly and Parliament. Sir, we see Ministry in the Government

of India first. After 72 years of Independence, we don't have any Ministry for the Other Backward Classes in the country. We are also requesting the Government to consider this request. In the President's Speech, they always say that Centre-State coordination strengthens the democracy. For strengthening the democracy, the Centre and State should walk together and depend on each other in the development process. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Now,Shri Subhas Chandra Bose Pilli. I think he is in the Lok Sabha Chamber.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI(Andhra Pradesh): Yes, Sir. I am in Lok Sabha Chamber.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): You can start, Subhas Chandra Boseji.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: I will speak tomorrow. I have given a letter to the hon. Chairman. Please permit me to speak tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Okay. Now, Shri Bikash Ranjan.

SHRI BIKASH RANJAN (West Bengal): Sir, I really take this opportunity to thank you for providing me an opportunity to speak on the Address of the President of India.

I think the President of India is the Head of the State but his Speech really relates to as if he is the Head of the Government. This Speech, therefore, in my humble understanding, relates to the so-called achievements of the Government and at the cost of the democratic principles. I just quote from the Hon. President's Speech. He has started his Speech quoting from a particular couplet from a well known poet from Assam but this has a very dangerous trend. He says, "India's grandeur is the ultimate truth. In one single consciousness, one thought, one devotion, one inspiration, let us unite; let us unite." This idea of one consciousness, one thought, one devotion is basically against the spirit of the Indian Constitution and it hits Indian constitutional morality. I am shocked; but this basic philosophical foundation ultimately led the hon. President to go ahead with his Speech which is not a complete speech. If I come to paragraphs 6 and 7 of his

Speech, he has not mentioned -- and deliberately he was not allowed to mention -- the hunger position of our country vis-à-vis the UN hunger index. We are very below, at the level which is a very alarming level. The people in our country are not getting proper food. Even the latest survey report made by Azim Premji University, Bengaluru says that the people are suffering from lack of nutrition, particularly the women and children are suffering from lack of nutrition but there has been a tall claim about the so-called *Garib* programmes.

Now I find that somebody who stands on behalf of the Government speaks high of Corona fight. I accuse this Government for not taking appropriate steps at the appropriate time to appease some personalities and thereby caused much harm to our society. In the month of December, there was an alarming indication of the spread of Coronavirus but the Government of India did not take any preventive measure, any step to ensure that the spread is not done and allowed the foreigners to come into our country and did not check them at the airport. The sudden declaration of lockdown with just a four-hour notice -- it has been mentioned by many speakers before me -- caused tremendous difficulties. Lakhs and lakhs of workers of the country started walking towards their hometowns. I find this particular thing missing here and it ought to have been mentioned in the speech of the hon. President. Therefore, the hon. President was not allowed to speak on the real sufferings of the people of our country. The actual sufferings ought to have been mentioned in the Address. It was described in detail in the newspapers. Everybody knows it from the newspapers and I do not wish to get into statistical details of the same, but that had caused a tremendous amount of spread of the infection. It is no good saying that we could check the number of deaths to less than one million. That is not the main point. There are other neighbouring countries we could take lessons from, who could arrest deaths in their own country by taking appropriate measures at the appropriate time. A mention of that is absent here, which shows that the Address was not really concerned about the plight of the Indian people.

Sir, another important aspect which has been touched upon by many is the peasants' struggle. I am sorry to say that in the speech of the hon. President, there is no mention of that. What he has mentioned is very unfortunate. He says that we respect peaceful movement and we condemn the 26th January incident. May I just read this out? This is very important. In paragraph 24, it is said, "After extensive consultation, the Parliament approved three important farm reform Bills." Sir, the fundamental point is, had there been extensive discussions, why did the question of

taking the Ordinance route arise? An Ordinance is ordinarily promulgated when there is an emergency or an extremely urgent situation. It is only then that an Ordinance is taken recourse to. If there had been such extensive discussions as the Government is claiming, why are they not able to answer the simple question as to why they went in for the Ordinance route? They could have straightway gone in for enactment through discussion in Parliament. You brought it in the Parliament only to get approval on the Ordinance. And, how did you discuss that? One of our fellow Members has described that and I am not going to waste my time on that. This caused a tremendous amount of dissension among the peasants as a whole. This is not the case of just Punjab and Haryana. It is no good citing the examples of Punjab and Haryana. Go down the States; go down the villages of every State. Everywhere there are demonstrations. Everywhere the peasants are very much aggrieved by these Acts. Now, someone was telling me that peasants are not so much educated. I wish to say that education does not mean having acquired a University degree. Education means lessons learnt from real life experiences. The peasants know where their shoe pinches and they are united. What are their demands? Why can't the Government accept their demands? Repeal and re-enact the laws. There is no legislative difficulty in that. Bring these laws to the Table, repeal and re-enact them. What do they want? They want MSP guaranteed for all and they also want a secured procurement. It is the basic duty of a Government to procure and provide food safety. We are talking about huge production made by the peasants. They could do that even in the absence of these amended laws. They were very keen to produce even earlier. Now, marketing is the duty of the Government. Peasants cannot be made traders. If you want peasants to be made traders, with the path that you have taken, you are really committing suicide. This is very unfortunate.

Sir, I find that there are many instances of statistics. Statistics, as I say, are a great lie. Statistical data sometimes do not reflect the real situation. So far as MSMEs are concerned, I find that allocation for MSMEs has been very meagre. The amount of Rs. 3,000 crore vis-a-viz 6.5 crore MSMEs does not absolutely meet the need of the people and the MSMEs, which is one of the big generators of employment. This has not been done. We have seen that under the *Deen Dayal Antyodaya Yojana* and the *Rashtriya Gramin Aajeevika Mission*, more than seven crore women entrepreneurs have become a part of the network of nearly 66 lakh self-help groups. These women groups have been provided bank loans worth three lakh and forty thousand crore rupees in the last six years. If you say, 'six years and the seven crore women', how much is the gain in one year? Therefore, these statistics

really do not reflect the realities of life. Has the hon. President mentioned that peasants' struggle is going on? No, he didn't. He, unfortunately, avoided that and the language he says is, "We respect..." This is the constitutional mandate. The Government cannot give us some concession by saying, "We respect...". You have to respect; you have to carry forward the constitutional obligations and the Constitution gives us the Right to Freedom of Expression. It is expected that we abide by the laws and rules with equal sincerity. Therefore, this equal sincerity should come more from the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Bikash*ji*, please conclude.

SHRI BIKASH RANJAN: How much time do I have?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Your time is only six minutes and you have taken eight minutes.

SHRI BIKASH RANJAN: Sorry; I was never told 'eight minutes'. Anyway, I am going to conclude. The Government and the ruling dispensation, sometimes, talk of Rabindranath Thakur(Tagore). I conclude with a particular poem from the Gitanjali which has received accolade from the whole world. It tells us what India was thought of and how India should be built up. May I read this? "Where the mind is without fear and the head is held high; Where knowledge is free; Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls;" I repeat it, " Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls; Where words come out from the depth of truth;" Mere words would not do. "Where words come out from the depth of truth; Where tireless striving stretches its arms towards perfection; Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;" We are saying that *Ram Mandir* will give us unity. We are all really talking of dead habits. "Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action; Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake." Let us enjoy that freedom where somebody will not be arrested because of speaking against the Government; where the intellectuals would not be described as urban naxals and put behind the bar. Let us think of that. Let us think of federalism whose foundation is unity in diversity and diversity in unity. You should not think that everything should be done by you and every credit should be claimed by you. This is done by people of the whole country. Try to respect them and give respect to them. Withdraw your farm laws; sit with them. You cannot invite them for negotiation by

putting concrete walls and by stopping their approach to the city. This is not the way, nor does a democratic Government do it. Therefore, I would appeal, through you, that this statement of the hon. President does not reflect the Indian realities. Therefore, I cannot support this.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) **:** मान्यवर, आपने इस अति गंभीर विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मान्यवर, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ**:**

"हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।"

मान्यवर, आज मुल्क में किसान के जो हालात हैं, आज इस देश में क्या हालत कर दी गई है? पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन पर हैं। उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गईं, आँसू गैस के गोले छोड़े गए, बूढ़े किसानों की आँखें फोड़ दी गईं, कड़कती ठंड में पानी की बौछारें की गईं। मान्यवर, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको गद्दार कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको अपमानित किया गया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा, ये किसान नहीं, आतंकवादी हैं, इनको शूट कर देना चाहिए। इनको शूट कर देना चाहिए और अगर दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती है तो मैं इनको जूतों से मारूंगा। मान्यवर, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। इस देश के अन्नदाता, जो अनाज पैदा करके आपका पेट भरते हैं, आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं! आप 11 दौर की वार्ता कर चुके हैं, सारी की सारी वार्ता फेल हो गयी। आप कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं! मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए दो रुपये भी नहीं हैं? अगर दो रुपये नहीं हैं तो हम लोगों से ले लीजिए, लेकिन किसानों को कॉल कर लीजिए। उनकी पीड़ा चरम पर पहुंच चुकी है। अब तक 165 किसानों ने अपनी शहादत दी है। आप गाज़ीपुर बॉर्डर पर जाकर देखिए, वहां आपको 97 साल के इलम सिंह मिलेंगे। उनके दो बेटे फौज में हैं, वे रो-रो कर कहते हैं कि मुझे इस उम्र में उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है, यह उनकी पीड़ा है। आप टीकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर जाकर देखिए, वे लोग पीड़ा के साथ कहते हैं कि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के वंशजों को, शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को, जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वालों के वंशजों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन अन्नदाताओं से आपकी क्या दुश्मनी है? आपने सब कुछ कर लिया, अब तो कम से कम उनके ऊपर दया कीजिए। ये तीनों काले कानून आपको वापस लेने ही पड़ेंगे, आपको इन्हें वापस लेना चाहिए। अब आपने जुर्म की इंतिहा कर दी। आप गाज़ीपुर बॉर्डर पर जाकर देखिए, वहां कंटीले तार, बड़ी-बड़ी कीलें गाड़ दी गई हैं, सड़कों पर 12-12 इंच की

कीलें गाड़ दी गई हैं। वहां देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ऐसी स्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती हैं। जब देश का शासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं, बेड़ियां बंधवाता है या देश की जनता को शत्रु समझने लगता है, तब ऐसी बेड़ियां लगवाता है।

आज इनके जुर्म के कारण हिन्दुस्तान के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत को रोना पड़ा और यह कहना पड़ा कि भाजपा के लोग हमें घेरकर लाठियों से पीटना चाह रहे हैं। आप यह करा रहे हैं! आप यहां डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप आज़ादी की बात करते हैं! आपने इस देश की हालत यह बना रखी है कि राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज करके पत्रकारिता को दबाने और कुचलने का काम किया है। हर तरफ जुर्म, हर तरफ एफआईआर और हर तरफ मुकदमे-- जो पानी पहुंचा रहा है, उस पर मुकदमा, जो डीज़ल दे रहा है, उस पर मुकदमा, जो खाने का इंतज़ाम कर रहा है, उस पर मुकदमा, एनआईए लगा दो, सीबीआई लगा दो, पुलिस लगा दो और जांच लगा दो। वे आपके देश के नागरिक हैं। आप कहते हैं कि किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया। हम बड़े समझदार हैं, आइए हम आपको किसानी बिल समझाएंगे। महोदय, इनकी समस्या यह नहीं है कि किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, इनकी समस्या यह है कि किसानों को यह बिल समझ में आ गया है और अब ये किसान तीनों काले कानून वापस चाहते हैं। आप स्वयं को बड़ा अकलमंद समझते हैं। भाजपा के लोगो, आप किसान को इतना मूर्ख मत समझिए, वे बिगड़ैल बैल की नाक में नकेल डालते हैं, आपकी सरकार की नाक में भी नकेल डाल देंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं आज यहां सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल रहे थे, वे कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2019 के घोषणापत्र में लिखा था, यह बिल कांग्रेस पास करना चाहती थी। जीएसटी की बात करो तो कहते हैं कि यह बिल तो कांग्रेस करना चाहती थी, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, लेकिन वे सांसद यह बताना भूल गए कि जब कांग्रेस यह बिल लेकर आयी थी, उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने बिल का विरोध किया था। कांग्रेस ने अगर वर्ष 2019 के घोषणापत्र में इस बिल को शामिल किया था, तो उनको तो 55 पर पहुंचा दिया। आपने तो उसको लागू कर दिया और इस देश की जनता आपको पांच पर पहुंचा देगी। अगर आप कांग्रेस के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, तो जनता को भ्रमित मत कीजिए, अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कर लीजिए- एक कांग्रेस-A हो जाएगी और एक कांग्रेस-B हो जाएगी । आप लोग समझें कि आप क्या कहना चाहते हैं, जनता तय कर लेगी।

मान्यवर, इस बिल में क्या-क्या लिखा है, वे बातें बताकर और कुछ अपनी बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करुंगा। इन बिलों में असीमित भंडारण की छूट दी गई है यह छूट क्यों दी गई है? दो साल से अडाणी की 100 एकड़ जमीन का land use change करने की application हरियाणा सरकार के पास पेंडिंग थी, लेकिन 7 मई को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उस समय उस land use को change करके 100 एकड़ जमीन पर अडानी जी को भंडारण, cold storage बनाने की छूट दी गई और 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए असीमित भंडारण और cold

storage बनाने की छूट दी गई। यह बिल किसानों के लिए नहीं लाया गया है, यह सरकार अपने चार पूंजीपति मित्रों के लिए यह काला कानून लेकर आई है, उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह काला कानून लाया गया है। यह सरकार 130 करोड़ लोगों की सरकार नहीं है, यह सरकार उन चार पूंजीपति लोगों की सरकार है, जिनके लिए यह कानून बनाती है। ये इनसे चंदा लेकर चुनाव लड़ने का काम काम करते हैं। यह सरकार ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है।

मान्यवर, दिल्ली के मुख्य मंत्री के बारे में इनकी तरफ से यह कहा गया कि ये किसानों का साथ दे रहे हैं। मैं सदन के अंदर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किसानों का साथ दे रही थी और आगे भी उनका साथ देती रहेगी। आपने हम से 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए मांगे, लेकिन केजरीवाल जी ने इन्कार कर दिया। हम उन लोगों के लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं और आप उनके लिए पानी के इंतज़ाम को रोक रहे हैं। हम वहां पर उनके लिए शौचालय का इंतजाम कर रहे हैं और आप उनके लिए शौचालय के इंतजाम को रोक रहे हैं। आप वहां पर लोगों के लिए पानी, खाना, शौचालय और इंटरनेट आदि पर भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे किसी दुश्मन देश के नागरिक हैं? आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? 26 जनवरी को एक माहौल बनाया गया, लाल किले पर हमला, लाल किले पर हमला। मान्यवर, किसान सात रूटों पर रैली लेकर निकले, तिरंगा रैली लेकर निकले और सातों रूटों पर कहीं भी किसानों ने कोई उपद्रव नहीं किया और न ही कोई हिंसा की। जो लोग लाल किले पर आए थे, वे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उन्होंने लाल किले पर हमला किया और तिरंगे का भी अपमान किया। दीप सिद्धू, जो भाजपा का नेता है, उसकी फोटो प्रधान मंत्री के साथ है, देश के गृह मंत्री के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं ने लाल किले का अपमान क्यों किया, तिरंगे का अपमान क्यों किया? मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज दीप सिद्धू भागता फिर रहा है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. एल. हनुमंतय्या) : संजय जी, आप conclude कीजिए।

श्री संजय सिंह : सर, सबको समय मिला है, मुझे भी थोड़ा और समय दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**... सबको समय दिया है, मुझे भी और समय दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): I have given sufficient time. मैंने आपको दस मिनट का समय दिया है।

श्री संजय सिंह : मान्यवर, दीप सिद्धू भाजपा नेता है, जिसने लाल किले पर हमला किया, जिसने तिरंगे का अपमान किया, वह फरार है। अपनी घिनौनी राजनीति के चक्कर में ये लोग कहां तक जा सकते हैं, जो सामने आया है, इसका यह सच है। आप MSP देने की बात कहते हैं। आप कहते हैं कि हम इस देश के किसान को MSP देंगे। यह बड़ी अजीब बात है। इस देश के किसान को MSP देने के नाम पर ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश की खबर के बारे में बता रहा हूं।

वहां पर धान क्रय केन्द्रों पर दस अधिकारियों के खिलाफ FIR हुई, क्योंकि क्रय केन्द्रों पर खरीद में MSP में गड़बड़ी की गई थी। इसी तरह से वहां पर एक रुपए किलो गोभी बिक रही थी, तो किसान ने अपनी गोभी पर ट्रैक्टर चला दिया। उत्तर प्रदेश में बरेली के अंदर कागज़ों पर तीन करोड़ की धान खरीद हो गई, लेकिन किसान का पता तक नहीं है। देरेक ओब्राईन साहब, जो यूपी में खरीद हुई है, वह भूतों की खरीद हुई है। वहां किसान का पता नहीं है, नाम दर्ज़ करके खरीद हो गई। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर चार साल में गन्ना किसानों के लिए गन्ने पर मात्र दस रुपये ही बढ़ाए हैं। आप न एमएसपी देना चाहते हैं, न किसान को उसकी फसल का दाम देना चाहते हैं। असीमित भंडारण की छूट देकर आपने पूंजीपति मित्रों को यह सुविधा दे दी कि वे सस्ते में किसान से अनाज खरीदेंगे।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please conclude, Sanjay ji.

श्री संजय सिंह : सस्ते में किसान से फल खरीदेंगे, सस्ते में किसान से सब्जियां खरीदेंगे, उनका बड़े-बड़े स्टोरेज में भंडारण करेंगे, जमाखोरी करेंगे और जब बाज़ार में फल, सब्ज़ियों और अनाज की कमी हो जाएगी, तब महंगे दामों में जनता को बेचेंगे। यानी आपने महंगाई को, जमाखोरी को, कालाबाज़ारी को इस बिल के माध्यम से legalize करने का, वैधता प्रदान करने का काम किया है। आपने इस देश में महंगाई बढ़ाने का काम किया है। इन सबका रास्ता आपने खोला है, इसलिए इन तीनों काले बिलों को वापस लिया जाना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you. Please conclude.

श्री संजय सिंह : अंत में, आपने बजट पेश किया। मान्यवर, मैं उन्हीं बातों को कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। सर, इन्होंने बजट पेश किया है। बजट के ऊपर और खरीद के ऊपर जो इनका बजट है, मैं उस पर चंद लाइनें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।

"धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे
कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे ।
अगर तुम यूं ही सोते रहे,
तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे,
वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे।।"

SHRI M.V. SHREYAMS KUMAR (Kerala): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to speak on this occasion.

Para 25 of the President's Address says, "The Government holds in high esteem the values of democracy and sanctity of the Constitution and that the Government has always respected Freedom of Expression and holding of peaceful

agitations." Sir, in the 2020 World Press Freedom Index, India is ranked abysmally low at 142 out of 180 countries. Even the military junta Myanmar is ranked above India at 139. Palestine is at 137. Monarchy countries like Oman and UAE are ranked at 135 and 131 respectively. It is a shame for this Government that no democracy is ranked as low as India at 142.

Rashtrapati can see how democracy is butchered just a few kilometres away from the Rashtrapati Bhawan at Singhu border. Our *anna dattas,* the *kisans,* on whom the Rashtrapati showers praise in his speech, are silenced and traumatised with multi-layered barricading, iron nails on road, barbed wires and iron rods between cemented barricades, reminding one of the horrific incidents of Tiananmen Square. None of the constitutional values are upheld by this dispensation. Rashtrapatiji in para 26 denounces farmers' protests as disrespect to constitutional values. It is the BJP Government which dishonoured the national monument, Red Fort, by handing it over to a private entity for five years for Rs. 25 crores. Sir, let me remind you that Article 51 A says that it is a fundamental duty of every citizen to value and preserve the rich heritage of our composite culture. They have dishonoured this fundamental duty by handing it over to a private group enabling these branding opportunities. They do not know the difference between a national monument and a commercial property. However, when some hooligans entered the Red Fort, which is an unfortunate incident, the dispensation first allowed them to enter and create mayhem only to raise the 'jingoistic' fervour later, and farmers are then called anti-nationals. Unfortunately, the President has not seen the sufferings of his fellow brethren, the *kisans,* the *anna dattas*, who are protesting just a few kilometres away from the Rashtrapati Bhawan. They are today insulted by the BJP dispensation by terming them as anti-nationalists. Internet is banned at the site of farmers' strike. This is draconian and unheard of in a democratic set-up. Several internet personalities have started raising voices against this.

Sir, the Preamble of our Constitution reads, "Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic". Parliament is no longer sovereign. Bills are passed for private ends. There is no socialism. In the name of free market economy, the Government is selling all its assets. Even the LIC is privatised. Next is, disinvestment of all Government-run PSUs and banks. The country is being mortgaged to private entities. Republic is a misnomer. Rashtrapati *ji* speaks a lot about *Atmanirbhar Bharat*. It is nothing but a catchy slogan aimed at hoodwinking the citizens. Even 80 per cent of the toys sold in India worth Rs.4,000 crore are being imported. We don't

even make those and we are saying *Atmanirbhar Bharat*. Let this Government know that *roti* cannot be downloaded from Google. It is the farmers who feed us. The rich gets richer and the poor gets poorer.

Sir, I would like to end my speech with a famous quote of Nigerian poet and Nobel Laureate Wole Soyinka. He says, 'The greatest threat to freedom is the absence of criticism.'

With this, I oppose the Motion of Thanks on the President's Address.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

SHRI K. VANLALVENA (Mizoram): Thank you so much, Mr. Deputy Chairman, for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address.

First of all, I want to emphasise serial No.72 of the President's Address which indicates the Union Government's policy for rapid development of the North East. Hon. President spoke about construction of road in the North East, especially in the State of Assam, along the Brahmaputra River. In addition to this, Modi *ji*'s Government has done many things in our State of Mizoram in the field of road construction. Modi *ji*'s Government has taken so many steps for the construction of roads that will be very helpful to implement Act East Policy such as construction of a 4-lane road from Silchar to Aizawl which is about to start. The Government of India is preparing for its tender. Construction of a 2-lane road from Aizawl to Champhai has started this year which will connect Indo-Myanmar Border Trade Centre at Zokhawthar. This Border Trade Centre has started some years ago, but due to coronavirus pandemic this Border Trade Centre has been closed maybe for 10-11 months. Construction of a 2-lane road will connect this Border Trade Centre near Myanmar boundary. Another is construction of a 2-lane road from Seling to Tuipang, which is one of the southernmost villages of Mizoram in the Myanmar border. Lawngtlai to Paletwa, Myanmar Seaport road, construction of a 2-lane road has been started. This Lawngtlai to Paletwa road will connect the road up to Bay of Bengal within Myanmar. This road will be very helpful not only to the people of Mizoram but also for the people of the whole of the North East. Moreover, Lunglei to Tlabung Indo-Bangla border trade route is ready for calling tender this month. The Central Government is ready to call tender for the construction of Lunglei to Tlabung road. Tlabung is situated at the boundary of Bangladesh, on the banks of Khawthlangtuipui

River. So, the hon. Prime Minister Modiji's Government is preparing to establish a new border trade centre here. The name of that village is Kawrpuichhuah, which is very near to Tlabung. It is on the bank of Khawthlangtuipui River. So, up to this village, the Union Government is preparing to construct a new road from Lunglei to Kawrpuichhuah. Construction of this road will be very helpful for the State of Mizoram. And, there is still another road which is Tripura-Aizawl National Highway-44A. Two-lane road is under construction. So, I express my heartfelt thanks to the hon. Prime Minister Modiji's Government for doing all these works in our State.

Mr. Deputy Chairman, Sir, in the meantime, I would like to express my hope for the construction of Indo-Bangla border road along the border fencing line because many Border Outposts of BSF and the surrounding villages have no road connectivity. I have visited these border places just before I came down here for the Session. I discovered that some villages have been put outside border fencing. About ten border outposts have no road connectivity from any part of India. It is situated just like an island. In addition to this, I would like to mention that it will be very important to establish new border road along the border fencing which will connect some villages and will also connect some border outposts of BSF.

Secondly, hon. Deputy Chairman, Sir, I would like to mention paras 3, 5 and 6 of the President's Address on how Modiji's Government encountered multiple problems during the time of Covid-19 pandemic. I hope we all know about Indo-China border problem, Indo-Pakistan border problem, major cyclone in several States, earthquakes, floods, locust attack, bird flu, Coronavirus, etc. All those different problems were faced by Modiji's Government last year. We all know that.

We all know what happened at Indo-China border last year. Standoff was a popular word throughout the country. Fear of China remains in the hearts of some people since Chinese aggression into Arunachal Pradesh in 1962 till 2020. However, I would like to emphasise that hon. Modiji's Government completely changed the mindset of those people who feared invasion by Chinese Army. Modiji's Government has completely changed the mindset of those people so that they could possess unwavering faith upon our Armed Forces. In the meantime, simultaneous challenges came to us of saving lives of the citizens and protecting the economy.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI K. VANLALVENA: Okay, Sir. In order to save the lives of our people, we had to close some institutions, some market places, shops, etc. and we had to stop vehicle movement.

1.00 P.M.

Even air service and railway line are to be stopped so as to save our own people but if we have done like this, it hampers the life of our economy. So, those kind of simultaneous problems have been happening since last year. In the meantime, Modi*ji*'s Government could survive in the midst of those different problems. As we all know, in the field of agriculture, farmers' production have been increased..... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, your time is over.

SHRI K. VANLALVENA: Okay, let me conclude hon. Deputy Chairman Sir. In the meantime, India has done the best in the field of fighting Coronavirus. Even in USA, only 60 per cent Corona positive cases have recovered but in India, 96 per cent Corona positive cases have recovered. Not only this, the Government of India could provide COVID-19 vaccine, which is its own production. It is a great thing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please end your speech now. You have already taken more time. Please.

SHRI K. VANLALVENA: Okay, let me conclude. So, I thank God our Lord Jesus Christ who led hon. Modi*ji*'s Government to attain such a great victory. Thank you.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान) : आदरणीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर संसद में अपनी बात रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

माननीय उपसभापति जी, आज देश जिन परिस्थितियों से गुज़र रहा है, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अर्थ नीति, देश का स्वास्थ्य - न केवल देश बल्कि दुनिया की अर्थ नीति और दुनिया का स्वास्थ्य, हम एक अलग प्रकार के चुनौती भरे क्षण में चल रहे हैं और यह संजोग देखिए कि आज हम 2021 के फरवरी महीने में देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, हम लोगों ने अभी-अभी गणतंत्र दिवस मनाया है। 21वीं सदी के दो दशक पार करके जब हम तीसरे दशक में जा रहे हैं, तो तीसरे दशक का पहला साल अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। कभी-कभी जब हम दुनिया की अर्थ नीति की समीक्षा करते हैं, तो कोई भी अर्थ

नीति हो - यदि हम विशेषकर अमरीका को क्वोट करेंगे, अगर उसका थोड़ा अनुशीलन करेंगे, तो पाएंगे कि पिछली सदी में अमरीका का जो ट्वेंटीज़ रहा है, उसको वहाँ के अर्थशास्त्रियों ने "रोरिंग ट्वेंटीज़" कहा है। यह कोई अमरीका को कॉपी करने की बात नहीं है, लेकिन एक संजोग देखिए कि अभी हमें जिस प्रकार का मौका मिला है और राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में उसका कुछ उल्लेख किया है, उससे लगता है कि हमारे लिए इस सदी का यह जो दशक है, इसमें "रोरिंग ट्वेंटीज़" के नाम पर दुनिया के इतिहास में हम कुछ लिखने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हम लिखेंगे कि देश का नेतृत्व करने वाले, विश्व के अद्वितीय जन नेता श्री नरेन्द्र मोदी आज देश के प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी में हैं। **..(व्यवधान)..**

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय**..(व्यवधान)..**

श्री धर्मेंद्र प्रधान : राजा साहब, प्रजातंत्र में आप जैसे वरिष्ठ नेता को मेरे जैसे व्यक्तियों के प्रति इतना तो**..(व्यवधान)..**

श्री दिग्विजय सिंह : मैं तारीफ कर रहा हूं। **..(व्यवधान)..**

श्री धर्मेंद्र प्रधान : मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। राजा साहब, अगर हम सब मर्यादा में रहें, तो अच्छा है। मैं आपसे सीखता हूं।

श्री उपसभापति : कृपया आपस में बात न करें। आप चेयर को सम्बोधित कीजिए।

श्री धर्मेंद्र प्रधान : लेकिन अगर मैं अपने नेता की प्रशंसा करूँ, जिसको विश्व मानता है, तो आपको इतनी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यह प्रजातंत्र का तकाजा है। राजा साहब, मैं yield नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका आदर करता हूँ। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*...

श्री धर्मेंद्र प्रधान : उपसभापति जी, इस सरकार की और विशेषकर इस नेतृत्व की एक अलग philosophy है। इसी सदन में और लोक सभा में मेरे नेता ने कई बार, एक बार नहीं कई बार कहा है कि अब तक जिनके हाथ में इस देश की जिम्मेदारी रही, सबने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और अभी हमें मौका मिला है। प्रजातंत्र में यह किसी की खैरात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आपको बहुमत मिला, तो इतना अहंकार क्यों है। उपसभापति जी, हमें ऐसा अहंकार नहीं है, यह विनम्रता है, यह हमारी जिम्मेदारी है, यह देश का mandate है। 2014 और 2019 में देश की जनता ने कल्याणकारी व्यवस्था चलाने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी को जिम्मेदारी दी है। यह किसी की खैरात नहीं है, किसी की दया पर हम यहाँ नहीं आए हैं, देश के गरीबों की दया पर हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारी कुछ रीति है, कुछ नीति है, कुछ हमारा चरित्र है, कुछ हमारी प्राथमिकताएँ हैं, मेरे प्रधान मंत्री के काम करने के कुछ तरीके हैं। यह सब तब महत्वपूर्ण हो जाता

है, जब हम आजादी के 75 साल पूरे करने से एक साल पीछे हैं। हमने पूज्य बापू की 150वीं जयंती इन दिनों में मनाई है। इसी साल नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का 125वाँ जन्मदिन अभी-अभी प्रधान मंत्री उनके कर्मस्थल, कोलकाता जाकर मना कर आए हैं और हमें सौभाग्य मिला कि हम उनके जन्मस्थान पर जाकर उनको प्रणाम करके आए हैं।

उपसभापति जी, 2014 में जब प्रधान मंत्री जी ने पहली बार NDA के नेता चुने जाने के बाद अपनी प्राथमिकताएँ गिनाई थीं, तो उन्होंने क्या कहा था, मैं आज इस चर्चा के अवसर पर उनका दोबारा उल्लेख करना चाहूँगा, यह नई बात नहीं है, लेकिन मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, "मेरी प्राथमिकता देश के गरीबों के लिए रहेगी, देश की महिलाओं के लिए रहेगी, देश के युवाओं के लिए रहेगी, कृषक के लिए रहेगी, वंचित वर्गों के लिए रहेगी, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए रहेगी, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के मित्रों के लिए रहेगी।" यह हमारी सरकार की नीति है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना हमारी नीति रही है। हमारा सरकार चलाने का मूलमंत्र रहा है - 'Minimum Government Maximum Governance'. उसी मंत्र के ऊपर गरीब को सबसे ऊपर रख कर, गरीब को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए हमने अपना कार्यक्रम चलाया, जिसके कुछ विषयों को अभी राष्ट्रपति जी ने अपनी सरकार के बारे में उल्लेख किया है। मेरा नेतृत्व, किसी को पीड़ा हो सकती है, निडर है, decisive है, निर्णय करता है। वे कोई भी काम हाथ में लेते हैं, तो slogan नहीं देते हैं, समयावधि में उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। उपसभापति जी, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने कहा कि मैं सभी पूर्व प्रधान मंत्रियों का आदर करता हूँ। मेरे नेता, अटल जी भी प्रधान मंत्री रहे, अनेक महानुभाव प्रधान मंत्री रहे, लेकिन बताइए कि किस प्रधान मंत्री ने प्रति माह राज्यों के सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर, भारत सरकार के सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर प्रगति मीटिंग चलाई है! प्रगति मीटिंग में कहीं रेल पटरी, जो पाँच दशक पहले शुरू हुई थी, जिसकी नींव रखी गई थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई थी, उनकी प्रगति देखी जाती है। कभी सिंचाई का प्रकल्प है, कभी कोई अभयारण्य का प्रकल्प है। पिछले दिनों में जिनके हाथ में दायित्व रहा, उन्होंने तो घोषणा कर दी, पीछे मुड़ कर देखा नहीं कि वह हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरे decisive, निर्णायक नेतृत्व ने प्रगति मीटिंग करके सबको चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का काम किया। हमने पारदर्शी सरकार चलाई। हमने जन-सहभागिता को आधार बना कर सरकार चलाई। जन-सहभागिता को एक जन-आंदोलन के रूप में, जन-सरोकार को ध्यान में रखते हुए हमने शासन चलाया। यह हमारी सरकार की रीति-नीति रही है। जैसा मैंने कहा कि गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता रही, कल्याणकारी राज्य हमारी प्राथमिकता रही। 42 करोड़ लोगों के जन-धन खाता खुले हैं। Toilets 10.7 करोड़ लोगों के बने हैं। अगर मैं एक विषय का उल्लेख करूँ, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन जब देश आजाद हुआ, तो देश में toilets एक प्रतिशत लोगों के पास थे, जब 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा गया, जब हमने महाआकाश में अपनी पराकाष्ठा दिखाई, तब देश में toilets दो प्रतिशत थे, जब हमने विश्व कप जीता, 1983 में, तब भी toilets की हमारी संख्या दो प्रतिशत थी। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके सामने 1998 के आंकड़े रखना चाहता हूं। वर्ष 2000 में जब हम नई सदी में पहुंचे, तब तक भी भारत में केवल 18% घरों में टॉयलेट बने हुए थे। 2014 में जब

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने काम-काज संभाला, तो 2 अक्टूबर, 2014 तक देश में केवल 39% घरों में टॉयलेट थे। आज यह आंकड़ा शत-प्रतिशत ODF के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर चुका है। यह प्रधान मंत्री जी के निर्णायक नेतृत्व का एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। भारत में 4 करोड़ लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है।

उपसभापति जी, अब मैं एलपीजी कनेक्शन के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा। प्रधान मंत्री जी ने एलपीजी कनेक्शन लगाने की जिम्मेदारी हमें दी थी। 2014 तक 13 करोड़ नागरिकों के घर में एलपीजी कनेक्शन था, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़ कर 29 करोड़ तक पहुंच रही है। हमारी सरकार की यह उपलब्धि है और यही time-bound decisive governance है। आज देश में एक नई उमंग खड़ी हुई है कि सभी घरों तक नल से जल पहुंचेगा। चाहे किसी भी पार्टी की राज्य सरकार हो, आज इस काम में वे सब भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने हर घर में जल पहुंचाने का देश से वादा किया है।

माननीय रवि शंकर प्रसाद जी यहां बैठे हुए हैं। हम लोगों ने 1,000 दिनों में भारत के 6 लाख गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने की जिम्मेवारी ली है। किसानों के कल्याण के लिए 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' और 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना' चालू की गई। हमारे जिन मित्रों ने पिछले दिनों शासन चलाया, वे 10 सालों में 70,000 करोड़ रुपये देकर किसान हितैषी बनने का बिल्ला लेकर घूम रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मेरे प्रधान मंत्री जी सालाना 70,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में DBT कर रहे हैं और इतना बड़ा काम बिचौलियों की मध्यस्थता के बिना हो रहा है। Agriculture loan की राशि बढ़ाई गई है। जब मैं 'प्रधान मंत्री मुद्रा योजना' और 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना' की बात कहता हूं, तो यह बात ध्यान में रख कर कहता हूं कि भारत में सबसे गरीब व्यक्ति का भाग्य तब परिवर्तित होगा, जब उसको उचित शिक्षा मिलेगी। यहां मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन देश को नई शिक्षा नीति तक पहुंचाने में पिछली सरकारों को 34 साल लग गए। मेरी सरकार, मेरे प्रधान मंत्री जी कोरोना के कष्टप्रद काल में भी देश के नौजवानों की आकांक्षा पूरी करने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, knowledge and employability skills को ध्यान में रखते हुए, new Education Policy लेकर आए हैं।

उपसभापति जी, अभी हमारे एक आदरणीय वरिष्ठ सदस्य यहां पर बोल रहे थे, जिनके ऊपर लम्बे समय तक एक राज्य की जिम्मेवारी रही है। अभी पिछले सप्ताह ही मैं उनके राज्य में गया था। मैं बैतूल ज़िले के बाचा गांव में गया था। वहां बैतूल ज़िले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में अनिल विखे नाम के गोंड समाज के एक व्यक्ति के घर में मुझे एक माता के, उनकी पत्नी के दर्शन करने का मौका मिला। मैंने उनसे कहा, बहन जी, आप हमें चाय पिलाएंगी? उन्होंने बड़े आदर के साथ हमें चाय पिलाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके घर तक इन योजनाओं के माध्यम से क्या-क्या पहुंचा है। महोदय, उन्हें 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के माध्यम से घर मिला, घर में बिजली पहुंची, 'उज्ज्वला योजना' के तहत एलपीजी कनेक्शन पहुंचा, सोलर लाइट पहुंची, सोलर कुकर पहुंचा, 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत टॉयलेट लगाया गया, पशुओं के लिए अलग घर बनाया

गया, 'अन्नपूर्णा मंडल' के नाम पर किचन गार्डन बनाया गया। वह गांव केवल 74 आदिवासी परिवारों का है, लेकिन इस छोटे से गांव में जल संरक्षण के लिए watershed system लगा है। हालांकि hand-pumps वहां पर पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन अभी उनमें उत्साह भरा है कि उनके यहां अपने नल में जल आएगा। स्वरोज़गार के लिए वहां पशुपालन, agriculture, SHG movement और बागवानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ-साथ पूरे गांव में concrete road एवं नालियों की व्यवस्था की गई है। आज उस गांव में दोगुनी खुशी है, क्योंकि उस गांव में 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत एक सर्वे हुआ है।

उपसभापति जी, यह नए भारत के एक गांव की तस्वीर है। इसमें किसी को भी पीड़ा क्यों होनी चाहिए? जब भारत अपने पैरों पर खड़ा होगा, तभी आत्मनिर्भर बनेगा। आज गांवों की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। आज विशेष तौर पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं पूर्वी भारत से आता हूं। उपसभापति जी, आप भी पूर्वी भारत से आते हैं। काशी से कोहिमा तक, चम्पारण से अंडमान तक, देश के एक-तिहाई लोग, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग पूर्वी भारत में रहते हैं।

महोदय, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अब तक जिन प्रधान मंत्रियों के हाथ में देश रहा है, उन सबने बढ़िया काम किया, लेकिन माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधान मंत्री होंगे, जिन्होंने पूर्वोदय की कल्पना की, पूर्वोदय के विकास के लिए योजना बनाई और पूर्वोदय के विकास के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ कैसे बढ़ाया, गुजरात से चुनकर रह सकते थे, लेकिन वह बनारस आए। पूर्व भारत की मुक्तशाला, विद्यानगरी काशी का प्रतिनिधित्व किया। आज पूर्वी भारत में क्या हो रहा है? उपसभापति जी, पूर्वी भारत के बारे में मैं अगर एक तथ्य आपके सामने रखूं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं मैंने गिनाईं, 'उज्ज्वला योजना' के आठ करोड़ में से पूर्वी भारत में, जब मैं पूर्वी भारत कहता हूं तो उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और समूचा पूर्वोत्तर, सिक्किम से लेकर त्रिपुरा तक, आठ करोड़ में से आधे से ज्यादा 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना' के लाभार्थी इन्हीं इलाकों में हैं। 'प्रधान मंत्री आवास योजना' में अगर देश में दो करोड़ आवास बने हैं तो 1.12 करोड़ इसी पूर्वी भारत में हैं। अगर टॉयलेट दस करोड़ बने हैं तो उनमें से साढ़े चार करोड़ पूर्वी भारत में हैं। अगर देश में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस चार करोड़ लगे हैं तो उनमें से एक करोड़ से ज्यादा पूर्वी भारत में हैं। 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना' की एक-एक किस्त में आज सालाना 16,217 करोड़ रुपये जाते हैं। एलपीजी कनेक्शंस, मैंने 'उज्ज्वला योजना' का पहले उल्लेख किया, लगभग 29 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस में से साढ़े 11 करोड़ पूर्वी भारत में हैं। 41 करोड़ 74 हजार जनधन खातों में से 16 करोड़ 22 लाख जनधन खाते पूर्वी भारत में हैं। अभी-अभी बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आदिवासी और जनजाति के बच्चों के लिए 20 करोड़ वाले एकल विद्यालय के लिए 38 करोड़ रुपया खर्चा होगा। पूर्वी भारत में आज 304 एकल विद्यालय खोले जा रहे हैं। यह केवल ह्यूमन डेवलपमेन्ट इन्डेक्स के लिए नहीं है। पूर्वी भारत से ज्यादा संख्या में माइग्रेन्ट लेबर आते हैं, रोज़गार वहीं हो, उसके लिए ख़निज, आयरन ओर, स्टील, कोयला, रोड सेक्टर, रेलवे, इंटरनेट, वाटरवेज़ और 'प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा' में तो हमने पहली बार पूर्वी भारत में नेचुरल गैस की पाइप लाइन जगदीशपुर से लेकर हल्दिया तक खींची है।

इतना ही नहीं है, बरौनी से पूरे नॉर्थ-ईस्ट के आठ राज्यों में प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर 'इन्द्रधनुष योजना' शुरू की गई है। पहली बार भारत सरकार ने पूर्वी भारत के विकास के लिए गैस पाइप लाइन के लिए तिजोरी से पैसा दिया है। यह प्रधान मंत्री जी की पूर्वी भारत के ढांचे के लिए तत्परता है। 'उड़ान योजना' में, उपसभापति जी मुझे लग रहा है कि मैं दो-तीन चीज़ों का उल्लेख और करूं। जमशेदपुर, झारसुगड़ा, दुर्गापुर, आपका पुराना राज्य दरभंगा, देवघर से आप जुड़े रहते हैं। असम का पासीघाट, अरुणाचल का पासीघाट, लोअर असम का रूपसी, डिब्रूगढ़ जिले का एक नया एयरपोर्ट है। बोलांगिर, अरुणाचल के ग्रीन फील्ड एयरफील्ड में है, इसलिए मैंने पूर्वी भारत के छः-सात एयरपोर्ट्स के नाम लिए, ये कोई पटना, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी ऐसे एयरपोर्ट्स नहीं हैं, प्रधान मंत्री जी की दूरदृष्टि है कि जब तक पूर्वी भारत पश्चिम और दक्षिण के बराबर नहीं होगा, भारत का समूचा विकास संभव नहीं है। इसीलिए इन सारे सैक्टर्स में आज निवेश किया जा रहा है। डीएमएफ, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सर्वप्रथम मैं कहूंगा, कुछ मित्रों को मेरी इस बात से पीड़ा हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में तर्क हुआ है, जब 2012-13 में देश एक विचित्र स्थिति में पहुंचा। आखिर ये नेचुरल रिसोर्स किसके हैं? ये ख़निज सम्पदाएं उस आदिवासी की हैं या नहीं हैं, यह उस राज्य के हिस्से में आएंगी कि नहीं आएंगी? उन राज्यों को क्या मिल रहा है? क्या सिर्फ रॉयल्टी ही उनका अधिकार है? उन राज्यों को क्या मिल रहा है? लोग कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी की क्या योजना है? मैं आपको बताता हूं कि क्या योजना है? सुप्रीम कोर्ट ने उन दिनों कहा – नेचुरल रिसोर्स के ऊपर मूल अधिकार भारत के नागरिकों का है। प्रधान मंत्री जी ने कैसे योजना बनाई है? हमारी सरकार ने पिछले छः सालों में कोयला हो, आयरन ओर हो, बॉक्साइट हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो या पेट्रोलियम रिसोर्स हो, इन सारी नीतियों में संशोधन किया। नीलामी की नयी व्यवस्था लायी। विशेष करके कोयला और आयरन ओर पूर्वी भारत की पूँजी है, बॉक्साइट पूर्वी भारत की पूँजी है। नयी नीलामी व्यवस्था लायी गयी। पहले तो बिना मूल्य के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कौन चिट्ठा में दे रहा था, उसकी आज मैं नकारात्मक बात नहीं करना चाहता हूँ। कौन पैरवी कर रहा था, कौन चिट्ठा में दे रहा था, किस पार्टी के ट्रेज़रार साहब के हाँ करने के बाद मंत्री जी उसका अनुमोदन कर रहे थे? यह आज विवाद का विषय हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह की बात नहीं कहना चाहता हूँ। हम नयी नीति लाये, ट्रांसपेरेंसी लाये, हमने नीलामी की। एक भी पैसा दिल्ली की तिजोरी में नहीं आता है। ओडिशा में नीलामी का पैसा ओडिशा के लोगों के कल्याण के लिए भुवनेश्वर की तिजोरी में जाता है, झारखंड का पैसा राँची में जाता है, बंगाल का पैसा कोलकाता में जाता है, वहाँ की सरकार के हाथ में पैसा खर्चा करने के लिए दिया जाता है। इन तीन राज्यों में भाजपा का शासन नहीं है। हमने विकास के कामों में कभी भेदभाव नहीं किया। आखिर गरीब किसके हैं - देश के गरीब हैं। उनको सशक्त करना है। मैंने जो कहा कि मेरी सरकार की कुछ नीतियाँ हैं, कुछ रीतियाँ हैं, मेरी सरकार की रीति-नीति कल्याण की है, गरीबों के कल्याण की है। उपसभापति जी, हमने इसको करके दिखाया।

उपसभापति जी, कोविड मैनेजमेंट के सम्बन्ध में कई चर्चाएँ हुईं। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन दो-तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। एक पूर्वी भारत से सम्बन्धित और एक... उसका मुझे साक्षात अनुभव कैसे हुआ, कोविड के कारण क्या गौरव आया, मैं आपको दो शब्दों में दो विषयों पर बताता हूँ।

प्रधान मंत्री जी ने 'आत्मनिर्भर भारत' की कल्पना की और उसमें 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना' चालू की, जब माइग्रेंट लेबरर्स पूर्वी भारत की ओर पहुँच गये, बिहार पहुँचे, बंगाल पहुँचे, झारखंड पहुँचे, ओडिशा पहुँचे, नॉर्थ-ईस्ट पहुँचे। तब चुनौती यह रही कि उनको कैसे सम्भालें। 50,000 करोड़ रुपये का बजट लगाया गया, 50 करोड़ man days का सृजन किया गया - देश के 116 जिलों में, जिनमें ज्यादातर पूर्वी भारत के हैं, हमने रोजगार की जिम्मेवारी ली। हमारे प्रधान मंत्री मुँह छुपाकर भागने वाले नेता नहीं हैं, देश को साथ लेकर समस्या से सामने से लड़ने वाले नेता हैं। हम कोरोना को आज इसीलिए हरा पाये।

आज कोरोना काल की उपलब्धि क्या है? उपसभापति जी, मैं बीच में प्रधान मंत्री जी का संदेश लेकर चार-पाँच महीने पहले कुवैत गया था। वहाँ के तत्कालीन राजा का देहान्त हो गया था। भारत का उनके साथ सम्पर्क अच्छा है। वे प्रधान मंत्री जी के निजी मित्र रहे। मैं उनके लिए शोक संदेश नये राजा जी के पास लेकर गया। नये राजा के स्वागत का पत्र और पुराने राजा का शोक पत्र लेकर मैं गया। मैं उनसे मिला, मुझे लगा कि अपने प्रधान मंत्री जी की नम्रता, उनके वक्तव्य को मैं pass on कर दूँ। मैं जब उठने लगा तब उन्होंने कहा कि आप थोड़ा बैठिए, आपके प्रधान मंत्री जी के लिए मेरा एक संदेश है, उसको आप थोड़ा पहुँचाइए। मैं थोड़ा बैठा, फिर उनके साथ चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम आपके आभारी हैं, आपके प्रधान मंत्री जी के आभारी हैं। मेरे प्रश्न पूछने से पहले उन्होंने कहा पूछो, क्यों? तब उन्होंने उत्तर दिया कि जब हम कोरोना के संकट में रहे, हमारे देश में डॉक्टर्स नहीं थे, हमारे देश में नर्सेज़ आपके देश से आती हैं, हमने आपके प्रधान मंत्री को फोन किया तो उन्होंने डॉक्टर, नर्स, दवाई, मास्क, PPE Kit, ये सब उपलब्ध करवाये, इसके लिए मैं आपके प्रधान मंत्री जी का बड़ा आभारी हूँ। उपसभापति जी, यह सुन कर मेरे रोंगटे खड़े हो गये। यह आभार प्रधान मंत्री जी के लिए नहीं था, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के प्रति था। यह सिर्फ कुवैत की कहानी नहीं है। बहुत से लोग हमें साम्प्रदायिक कहते हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि मैं तेल विभाग का काम देखने के कारण खाड़ी के देशों में जाता हूँ। मैं on record कहता हूँ कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की विश्वसनीयता मुस्लिम राष्ट्रों में, खाड़ी के देशों में जितनी है, शायद भारत के किसी प्रधान मंत्री को इतना सौभाग्य नहीं मिला है। अभी कोरोना ने उसको और ऊँचाई तक पहुँचाया है। यह प्रधान मंत्री जी की कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह 130 करोड़ भारतीयों की उपलब्धि है।

उपसभापति महोदय, हम एक नयी दुनिया में पहुँच रहे हैं। आज वैक्सीन की तो नयी कहानी आयी है। हमारे नेतृत्व को विश्व का नेतृत्व आशा की नज़र से देख रहा है और जब विपत्ति आती है, उस समय सबके चेहरे ध्यान में आ जाते हैं। उपसभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। जब विपत्ति आती है, तब सबके चेहरे ध्यान में आ जाते हैं। संपन्न देश कनाडा किसका पड़ोसी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कनाडा की अपेक्षा भारत के प्रति है, खाड़ी के देशों की अपेक्षा भारत के प्रति है। ब्राजील, लैटिन अमेरिकन कंट्री किसके पास है, मैं यह कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जेयर बोल्सनारो जी यूरोप छोड़ कर भारत के प्रधान मंत्री को धन्यवाद कहते हैं - यह मेरे नेतृत्व की पराकाष्ठा है, यह मेरी रीति और नीति है।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी के आदेश पर ऊर्जा विभाग का काम देखता हूँ। अभी किसानों के बारे में बहुत बातें कही गईं। ठीक है, यही प्रजातंत्र का तकाज़ा है। जोर-जोर से बोलने से, नाटकीय ढंग से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है या सत्य असत्य में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तथ्य के आधार पर तर्क होना चाहिए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने ऊर्जा से संबंधित कई सारे विषयों के बारे में कहा। प्रधान मंत्री जी भारत में एनर्जी जस्टिस लाने के लिए कटिबद्ध हैं। सस्ते दामों पर एनर्जी मिले, सबको एनर्जी मिले, efficient energy मिले, energy efficiency रहे, यानी बिजली आकर कट न जाए, ऊर्जा की स्वच्छता रहे, ऊर्जा की security रहे - इसी का नाम है एनर्जी जस्टिस। विश्व नरेन्द्र मोदी जी के एनर्जी जस्टिस मॉडल की कॉपी कर रहा है। उसमें मूल बिन्दु क्या है? मैं एनर्जी से संबंधित सारे विषयों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन alternative energy के बारे में कहना चाहता हूँ, जिसके बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण और बजट में थोड़ा उल्लेख किया गया है।

Alternative energy के लिए भारत ने International Solar Alliance बनाया। हाइड्रोजन मिशन बना कर हम हाइड्रोजन इकोनॉमी को खड़ा करने में विश्व का नंबर एक देश बनने वाले हैं। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कहते हैं। हमारे देश में सोलर एनर्जी को कैप्चर करना, bio-fuels, biogas को एनर्जी में परिवर्तित करना और उसी में से दुनिया के विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार, हाइड्रोजन बनाना, उसी में हमारे ट्रांसपोर्टेशन और उद्योग-धंधे को बिना पर्यावरण को खराब करते हुए चलाने की हिम्मत नरेन्द्र मोदी जी में है। हम आज यह सपना देख रहे हैं। उसका लाभ किसको मिलेगा?

महोदय, अभी एमएसपी के बारे में बहुत तर्क और तथ्य रखे जा रहे हैं। एमएसपी को कानून में क्यों नहीं लाया जाता था? क्या आप कभी एमएसपी को कानून में लाये थे? आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके खानदान की चार-चार पीढ़ियों को देश संभालने का मौका मिला, आपने अनेक राज्यों को अपनी जागीर समझ कर शासन चलाया, लेकिन आप इसको कानून में कब लाए? आप 2013-14 में शासन छोड़ कर गए।

महोदय, मैं तीन commodities का नाम लेना चाहता हूँ - गेहूँ, धान और दलहन। आपने 2013-14 में इन तीन commodities में कितना एमएसपी दिया था? आपने 2013-14 में धान में 63 हज़ार करोड़ रुपए का एमएसपी दिया था, अभी हमने 2020-21 में 1,72,752 करोड़ रुपए का एमएसपी दिया है। कल विजय पाल सिंह तोमर जी इसका उल्लेख कर चुके हैं, मैं इसको दोहरा रहा हूँ। कुछ लोगों को सत्य सुनने में कष्ट होता है। सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य को सुनने से ही मोक्ष मिलेगा।...**(व्यवधान)**... आपने 2013-14 में गेहूँ में 33,874 करोड़ रुपए का एमएसपी दिया था, जब कि हमने इसी साल 75,050 करोड़ रुपए का एमएसपी दिया है। दाल तो nutrition होती है, यह तो कार्बो होती है, यह व्यक्ति की ऊर्जा के लिए आवश्यक है। आपने कितनी दाल खरीदी थी? आप इतने लंबे-लंबे भाषण दे रहे थे, गला फाड़ कर भाषण दे रहे थे, आपने दाल में 236 करोड़ रुपए का एमएसपी दिया था और मोदी जी ने पिछले साल 10,500 करोड़ रुपए का

एमएसपी दिया है। आप हमसे प्रश्न पूछते हैं कि एमएसपी कहाँ गया? आपके समय में, एक साल में कुल मिला कर 97,110 करोड़ रुपए का एमएसपी दिया गया था और हमारी सरकार में एक साल में वह संख्या बढ़ कर लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए हो गयी है। आप हमसे प्रश्न पूछते हैं, काम करने वाले से, ईमानदार व्यक्ति से, किसान हितैषी से प्रश्न पूछते हैं!

महोदय, मेरे मित्र प्रसन्न आचार्य जी, हमारे ओडिशा से आते हैं, किसान बैकग्राउंड से आते हैं, कल इन्होंने अपनी बात रखी थी। मैंने आज ओड़िया अखबार में पढ़ा। इन्होंने कहा कि आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? प्रसन्न जी, आप वरिष्ठ संसद सदस्य हैं। आपके साथ युवा साथी, सस्मित भाई भी हैं। आप दोनों पढ़े-लिखे हैं, मेरे राज्य के दो रत्न हैं। आप स्वामीनाथन कमिटी की रिकमंडेशंस थोड़ा ठीक से पढ़ लेते। हमने स्वामीनाथन जी की कमिटी की रिकमंडशंस को लागू किया है, मोदी जी ने लागू किया है, डेढ़ गुना आमदनी के लिए प्रावधान किए हैं। आप उसे थोड़ा पढ़ लेते। आप हमारी बात छोड़ दीजिए। आपको मोदी जी पर भरोसा नहीं है, आपको धर्मेंद्र प्रधान पर कम भरोसा है। मैं आपका प्रतियोगी भी हूँ और प्रजातंत्र में इतना होना ही चाहिए, लेकिन मैं सस्मित पात्रा जी से कहना चाहता हूँ कि आप अभी भाषण देंगे, उससे पहले मेरा अनुरोध रहेगा कि स्वामीनाथन जी ने इस कमिटी की रिकमंडेशंस को लागू करने के बाद क्या कहा, आप उसे पढ़कर थोड़ा ईमानदारी से भाषण दीजिएगा। प्रसन्न भाई, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरी आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। आप तो विद्वान हैं, कम से कम आप तो तथ्य सामने रखते और गुमराह नहीं करते।

दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि alternative energy के लिए किसानों के साथ संपर्क किया गया है। मैं इसी विषय पर आकर अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब अटल जी सरकार में थे, तब उन्होंने कहा कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। इसके लिए नीति भी बनी, लेकिन जब अटल जी गए, तब नीति को भी खटाई में डाल दिया गया। यह हमने वर्ष 2014 में आकर देखा और पीएम ने कहा कि हमें फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, इससे किसानों के पास पैसा जाएगा, गन्ना किसानों के पास पैसा जाएगा। इसमें हमने पाया कि 2012-13 में 35 करोड़ लीटर एथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने के लिए खरीदा था। यह हमारी आवश्यकता का 0.67 परसेंट था, यानी एक परसेंट से भी नीचे था और उसका मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपए था। उपसभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले साल हमने एक योजना बनाई और इसी साल -- मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ, मन की बात नहीं कह रहा हूँ, कहानी नहीं कह रहा हूँ, गप्पें नहीं मार रहा हूँ, बल्कि तथ्य कह रहा हूँ। एमएसपी के विषय पर चिल्लाने वाले लोग थोड़ा सुनें कि मोदी जी का क्या विज़न है। हमने 2020-21 में 325 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदने की योजना बना ली है और खरीदना भी शुरू कर दिया है, जिसका मूल्य 20,000 करोड़ रुपए होगा। यह हमारी आवश्यकता का साढ़े आठ परसेंट पूरा करेगा। इसको हम आगे आने वाले दिनों में 20 प्रतिशत तक ले जाएंगे। इसके साथ ही, एथेनॉल, कम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए 5,000 कारखाने लगने वाले हैं। हमने "गोबर-धन योजना" भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत गोबर, खेतों में जो बंजर वस्तुएं हैं, शहरों का जो वेस्ट है, जंगलों का जो वेस्ट है, बायोमास में जो कार्बन है, सबको एनर्जी में परिवर्तित किया जाएगा। चंद दिनों में गाज़ीपुर जैसे

कचरे के ढेर को साफ कर दिया जाएगा। उससे हम जो एनर्जी बनाएंगे, उसी से किसानों के खाते में एक लाख करोड़ रुपए की एडिशनल इनकम देंगे और इसी से किसानों की आमदनी दुगुनी होगी। यह हमारी सरकार का विज़न है, यह हमने करके दिखाया है।...**(व्यवधान)**... कुछ लोगों को इसमें हैरानी लग रही है। खुद तो उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को बातें सुनाईं और उनके खानदान की कहानी सुनाई। जो लोग सोने का चम्मच मुंह में लेकर जन्मे हैं, उन्हें यह कैसे पच सकता है कि कोई चाय बेचने वाला, जिसकी माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपना परिवार चलाया था, ऐसे परिवार से संबंधित कोई लड़का देश का कामकाज संभालेगा, प्रधान सेवक बनेगा? ऐसा व्यक्ति किन लोगों की चिंता करेगा? कुछ लोगों को इससे पीड़ा हो रही है। सोने का चम्मच मुंह में लेकर जन्म लेने वाले सामंतवादी लोगों को आज पीड़ा हो रही है, इसलिए आज वे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इस देश के प्रजातंत्र का जो भगवान है, वह उन सबको देख रहा है। उपसभापति जी, मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

महोदय, ओडिशा के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज समूहों के एक महान प्रेरक एवं संत कवि भीमा भोई थे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसकी उक्ति यूनाइटेड नेशंस में भी लिखी गई है।

*"Let my life remain inglorious, let the world achieve salvation."

महोदय, भारत के विचार वसुधैव कुटुम्बकम् के हैं। हमने कोरोना काल में विश्व को एक माना, मानवता को एक माना। हमने यह तय किया है कि अगर हम भारत के गरीबों का कल्याण करेंगे, तो विश्व का कल्याण होगा और अगर उसमें पूर्वोदय की चिंता की जाएगी, पूर्वोदय में अर्थनीति का विकास किया जाएगा, रोजगार की चिंता की जाएगी, वहाँ के स्वाभिमान, अधिकार के बारे में चिंता की जाएगी, तब देश का विकास होगा। भीमा भोई की यही philosophy भारत के अनेक संतों ने अपनी-अपनी भाषा में दी है और यही हमारी सरकार का, नरेन्द्र मोदी सरकार का ध्येय वाक्य है।

आज ऐसी ही एक सरकार इस संकट के क्षण में, इस संधि में देश का शासन संभाल रही है, सेवा कर रही है। हमारा देश यशस्वी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी। माननीय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (हरियाणा) **:** उपसभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान चल रहे किसान आंदोलन से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज चार फरवरी को

---

* English translation of the original speech delivered in Odia.

किसान आंदोलन का 72वाँ दिन है। इस किसान आंदोलन में पूरी सर्दी-बारिश में लाखों की तादाद में लोग शामिल हैं। इस दौरान, सरकार और किसान के बीच बातचीत के बेनतीजा 11 राउंड हुए। फिर भी, आज जो स्थिति है, उसमें टीकरी बॉर्डर पर पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक चार-पाँच लेन, 17 किलोमीटर धरना, सिंघू बॉर्डर पर पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 21 किलोमीटर धरना, गाज़ीपुर बॉर्डर तथा बाकी अलग-अलग जगहों पर कई लाख लोग इन धरना स्थलों पर आज भी अपने मन में विश्वास रखे शांति और संयम से बैठे हैं।

पिछले 72 दिनों में इन धरना स्थलों से 194 किसानों के शव, जिन्होंने अपनी जान कुरबान कर दी, शहादत दे दी, अपने-अपने गाँवों में वापस लौटे हैं। कोई पूछ रहा था कि वे कौन हैं? यह वह लिस्ट है, जिसमें उनके गाँव का नाम है, उनके परिवार का नाम है तथा इसमें यह भी लिखा है कि उनका कौन-सा भाई चीन की सीमा पर तैनात है, उनका कौन-सा भाई पाकिस्तान की सीमा पर तैनात है, इसमें उन सबके नाम हैं। मैं इसको सभा पटल पर रखना चाहूँगा। यमुनानगर के स्वर्गीय रणदीप सिंह, गुन्दियाना गाँव के गढ़ी गुजरान, करनाल के स्वर्गीय राजेश चहल, जिसका भाई आज भी लद्दाख में तैनात है। पाई के स्वर्गीय अजय ढुल, बड़ोदा गाँव के स्वर्गीय भाई अजय कुंडु, जिनके घर मैं गया। मैं इनके परिवारों से मिलने गया। उनके घर पर उनकी विधवा और तीन बच्चे हैं। उनकी विधवा इतनी पढ़ी-लिखी भी नहीं है कि वह कोई नौकरी कर पाएगी। उनकी तीन लड़कियाँ हैं। वे तीनों अभी स्कूल में हैं, unmarried हैं। उनकी शादी कैसे होगी, उनके लिए कैसे व्यवस्था होगी? "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का नारा देने वाली सरकार, उनकी बेटियों को कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा? सैकड़ों जानें चली गईं, मगर सरकार के मुँह से संवेदना का एक अक्षर नहीं निकला। आज भाजपा की तरफ से जो लोग बोले, मैंने उन सभी के वक्तव्य को ध्यान से सुना। इन 194 परिवारों के लिए संवेदना का कोई शब्द कहना तो दूर की बात है, उनका जिक्र तक नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मेरे साथ लोक सभा में 15 साल तक थे, जब वे बोल रहे थे तो उन्होंने जरूर एक किसान का जिक्र किया, जिसने 26 जनवरी को अपनी जान गँवाई। प्रचंड बहुमत का अहंकार भी दिखाई दिया, कहा कि लोग हमारे साथ हैं, मगर इन इलाकों के अंदर यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में मुख्य मंत्री अपने गृह क्षेत्र में या उप मुख्य मंत्री अपने गृह क्षेत्र में कोई कार्यक्रम भी नहीं कर पाए हैं और न कर पा रहे हैं। हरियाणा के अंदर उपचुनाव में सरकार को हार का मुँह देखना पड़ रहा है, जबकि सरकार के अभी चार साल बाकी हैं। इस सरकार के पास जनता का कितना विश्वास है!

उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जिन पर ये धरने चल रहे हैं, वह मेरा गृह क्षेत्र है, मैं वहीं से आया हूँ। मैं इन धरना स्थलों पर गया हूँ, मैंने एक-एक ट्रॉली के अंदर झांककर किसानों से बात की है और मैं उनके घरों में भी गया हूँ। सर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं सदन के बीच में सच्चाई रखना चाहता हूँ, केवल सच्चाई रखना चाहता हूँ। हम इस स्थिति में कैसे पहुँचे? 5 जून, 2020 को कोरोना आपदा के बीच में अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश, जिनकी आवश्यकता तब होती है जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो, जैसा अभी देरेक ओब्राईन जी ने भी कहा। सामान्यतः जब दोनों हाउस किसी बिल को पास करते हैं, तो उस

पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं और तब वह ऐक्ट बनता है। अध्यादेश पर जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए, कानून लागू हो गया और उसके बाद दोनों सदनों को केवल एक रबड़ स्टैम्प की तरह उसको पारित करने के लिए प्रयोग किया गया। पंजाब में आंदोलन शुरू हो गया। हरियाणा और पंजाब में 6 महीने तक आंदोलन चलता रहा, कहीं पिपली में लाठी चार्ज हुआ, तो कहीं पंजाब के एक-एक टोल पर किसान बैठे, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई और 6 महीने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से उन किसानों ने फैसला किया कि रामलीला ग्राउन्ड में जाकर धरना देंगे। आज कुछ लोग पूछते हैं कि यातायात की इतनी परेशानी हो रही है, ये लोग बॉर्डर पर बैठे हैं- ये बॉर्डर पर बैठने नहीं चले थे, ये रामलीला ग्राउन्ड-- वही रामलीला ग्राउन्ड, जहां सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है, जहां देश की सरकार के विरोध में बड़े-बड़े आंदोलनों की गवाही रामलीला ग्राउन्ड देता है, जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन तक-- वहां धरने पर बैठने के लिए आना चाहते थे। वे शांतिप्रिय तरीके से चले, वे जैसे ही हरियाणा की सीमा में आये, उस समय कोई provocation नहीं था। वहाँ की सरकार हमलावर हो गई। किसान शांति से जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि उन्हें रोक लेंगे, मगर यह वही खून है जो देश की सीमा पर दुश्मन की गोली और गोलों के सामने छाती अड़ाये खड़े हैं, उनसे पीछे नहीं हटते। सरकार की लाठियों से, आंसू गैस से और वाटर कैनन से ये पीछे नहीं हटने वाले थे। ये चलते गए और बढ़ते गए। 25 नवम्बर को ये दिल्ली की सीमा पर पहुंचे, वहां देश की राजधानी की सीमा सील कर दी गई और वहां से धरना शुरू हुआ। उसके बाद सारी सर्दी बातचीत पर बातचीत, तारीख पर तारीख, बेनतीजा बातचीत हुई। आखिरी दौर में जब 11वां राउंड हुआ तो सरकार ने अपनी तरफ से एकतरफा बातचीत बंद करके उन्हें अपमानित किया। सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि 5 घंटे तक बैठे रहे और 5 घंटे के बाद उनको टेलीफोन पर बताया गया कि सरकार की तरफ से बातचीत समाप्त हो चुकी है। उसके बाद वे उठकर चले गए।

महोदय, 26 जनवरी की घटना का ज़िक्र हुआ। 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ भी हुआ, वह असहनीय है, कहीं कोई उपद्रव होता है, वह असहनीय है। उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाये जाएं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी होनी चाहिए, लेकिन न्याय का तकाज़ा है, 'दोषी तो बचे नहीं, मगर निर्दोष फंसे नहीं'। हमारे देश में यह न्याय की व्यवस्था है। जब 26 जनवरी की घटना हुई तो इस घटना की निंदा सारे किसान संगठनों ने की। उन सब ने अपने आपको इस घटना से अलग कर दिया और कहा कि जो दोषी हैं, उनके खिलाफ निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच हो। तरह-तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कई लोग कुछ राजनीतिक दलों से भी संबंधित हैं, कई लोग कइयों के इलैक्शन एजेंट भी रहे हैं, मगर मैं आज उस विषय में नहीं जाना चाहता। उनके नाम सामने आ रहे हैं। सारे तथ्य सामने आयें, दोषियों को सज़ा हो, यह सारे किसान संगठनों ने कहा है। उनकी बात पर यकीन किया जाना चाहिए, इसलिए किया जाना चाहिए कि ये ढाई महीने से बैठे हैं, मेरे इलाके में बैठे हैं, मेरे गृह क्षेत्र में बैठे हैं, लाखों की तादाद में बैठे हैं। उपसभापति महोदय, आप पुलिस थानों में पता करा लीजिए कि ढाई महीने में किसी को तंग करने की बात तो दूर, किसी की तरफ हिंसा की बात तो दूर, किसी एक रेहड़ी वाले से एक मूंगफली और एक केला भी अगर इन किसानों ने छीना हो और उनकी complaint पुलिस के पास आयी हो या 26 जनवरी को भी किसी दिल्ली के थाने में कोई दुकानदार या रेहड़ी वाला पहुंचा हो

और शिकायत की हो कि किसी किसान ने एक मूंगफली भी ली हो। आप वहां जाकर पता कीजिए, लोग कहेंगे कि किसान जहां बैठे हैं, उन्होंने अपने साथ-साथ हमारे लिए भी भोजन की व्यवस्था की है। इनकी बात पर इसलिए भी यकीन किया जाना चाहिए कि इन धरनों से लगभग 194 लाशें जब वापस गयीं, आदमी विचलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस सदन को बड़े-बड़े किसान आंदोलनों की याद दिलायी और कहा कि हर आंदोलन में सरकार झुकी थी, चाहे वह ब्रिटिश सरकार हो या आज़ाद भारत की सरकार हो। यह आंदोलन इसीलिए अलग है, क्योंकि सरकार झुक नहीं रही है। एक और वजह से यह आंदोलन अलग है, चाहे वर्ष 1905 का पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन हो, चाहे वह चम्पारण का सत्याग्रह का आंदोलन हो, चाहे वह गुजरात का बारदोली का आंदोलन हो, किसी आंदोलन में इतने किसानों ने अपनी जान कुरबान नहीं की, जितनी इस आंदोलन में किसानों ने अपनी जानें कुरबान कीं। ये लोग विचलित नहीं हुए और इन धरनों से इनके लोगों की लाशें उनके अपने गांवों में जाती रहीं, लेकिन ये लोग शांति से और संयम से बैठे रहे। इन सब बातों से इनकी नीयत का देश को अंदाजा लगाना चाहिए। न्याय का तकाज़ा था कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, लेकिन इस घटना के बाद क्या हुआ? इस घटना के बाद निर्दोष लोगों, किसानों व पत्रकारों को निशाना बनाया गया और बड़े-बड़े षड्यंत्र व साज़िशें रची जाने लगीं। किसान की आवाज़ को कुचलने के लिए प्रचारतंत्र हमलावर हो गया, प्रचारतंत्र झोंक दिया गया। आज यह प्रचार से, प्रचार के लिए, प्रचार द्वारा हो गया, यह प्रचारतंत्र हो गया है। आज यह प्रजातंत्र नहीं है, प्रचारतंत्र है। जो लोग इन धरनों पर बैठे हैं, उनको देशद्रोही बताया गया। यह भी कहा गया कि ये लोग आतंकवादी हैं। ये चीन, पाकिस्तान से funded हैं, गद्दार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो बाप यहां धरने पर बैठा है, जिसको गद्दार कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है, उसका अपना बेटा चीन की सीमा पर तैनात है। आज मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि अगर वह गद्दार है, तो उसका बेटा क्या है? मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं कि यह जो दिल्ली के आसपास का इलाका हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान है, यह "जय जवान, जय किसान" को चरितार्थ करती हुई भूमि है। मैं इस भूमि का बेटा हूं और मैं एक किसान का बेटा हूं। यदि हरियाणा की बात करुं, तो आज भी देश का हर दसवां सैनिक हरियाणा से है। आज हरियाणा का किसान मेहनत करके देश का 20 प्रतिशत खाद्य भंडार भरने का काम करता है। चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हों या कॉमनवेल्थ खेल हों, हरियाणा के खिलाड़ी देश के लिए 40 प्रतिशत मैडल लाने का काम करते हैं। जब ओलंपिक में और एशियाई खेलों में जिस किसान का बेटा देश का झंडा ऊंचा करे, देश की सीमाओं से तिरंगे में लिपट कर शहादत देकर वापस आए, आज उस किसान को तिरंगे के ऊपर उपदेश दिए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे ज्यादा देशभक्त और कौन हो सकता है? मैं अपने इलाके बारे में बताना चाहता हूं। मेरे गृह क्षेत्र में पिछले हफ्ते तीन dead bodies आईं, एक अरुणाचल से, एक लद्दाख से। बेरी के अंदर सिवाना गांव है। वहां का BSF का जवान, जिसका नाम सचिन था, शहीद हो गया। इसी तरह से गांव जूडी कोसली के अंदर शहीद दीपक कुमार यादव और खड़खड़ी गांव के अंदर शहीद कैप्टन जगतार सिंह भी शहीद हो गए। इन तीनों जवानों की बॉडी उनके घर वापस आई। ये तीनों बॉडी देश की सीमाओं से वापस आईं। इन्हीं गांवों में दिल्ली की सीमाओं से एक दर्जन किसानों के

परिजनों की डेड बॉडीज़ भी वापस गईं। दुर्भाग्य यह है कि उस जवान को और उस किसान को आमने-सामने खड़ा कर दिया गया है। उनके बीच में कंक्रीट की दीवार और कीलें लगा दी गई हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चहता हूं कि आपने दिल्ली की सीमा पर लगी हुई ये कीलें लोकतांत्रिक मूल्यों के ताबूत में सियासत की कीलों के रूप में लगाई हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ह्रदय से यह भी कहना चाहता हूं कि लाठीतंत्र कभी भी लोकतंत्र को नहीं हरा सकता। देश का अन्नदाता कभी धनाढ्य और उद्योगपतियों का गुलाम नहीं बन सकता। सरकार ने इन नफरत की कीलों उगाया है, जो नफरत की कीलों की खेती की है, इसकी कटाई भी किसान अपने प्यार की दरांती से करना जानता है। इन सबके बाद भी सच सामने आएगा, क्योंकि सच में ताकत है। आज मेरे पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है। आपके इंटरनेट, आपकी दीवारें, आपके पहरे, आपकी कीलें, सच को रोक नहीं पाएंगी, सच एक दिन जरूर आएगा और हम अन्याय की लड़ाई जरूर जीतेंगे।

प्रधान मंत्री जी की तरफ से तीन-चार दिन पहले एक बात आई थी और एक आशा जगी थी कि मैं दूर नहीं हूं, मैं बहुत नज़दीक हूं, एक टेलीफोन कॉल का इंतजार है। कुछ आशा जगी थी, लेकिन उसके चार-पांच दिन बाद विपरीत हुआ। जैसे ही प्रधान मंत्री जी ने कहा, वैसे ही अगले दिन सीमेंट की मोटी-मोटी दीवारें, पन्द्रह-पन्द्रह लेयर की बैरिकेडिंग, हज़ारों की तादाद में हथियारों से लैस पुलिस बल और यहां तक कि इंटरनेट, मेट्रो, बिजली, पानी और शौचालय, जो temporary toilets लगे हुए थे, उन facilities को भी प्रधान मंत्री जी की बात के तुरंत बाद वहां से हटा दिया गया। 'स्वच्छ भारत' का नारा देने वाली सरकार वहां से शौचालयों को भी हटाने का काम कर रही है, जहां इन धरनों पर लाखों किसान डटे हुए हैं। जब दुश्मन की फौज को भी surrender कराते हैं, तो वहां भी पानी का और शौचालय का इंतज़ाम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन हैं? प्रधान मंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम किसान के नज़दीक हैं, बस एक फोन कॉल दूर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन है, जो पिछले तीन-चार दिन से प्रधान मंत्री जी और किसान के बीच में दूरियां पैदा कर रहा है? ये किसान देश की राजगद्दी पर कब्जा करने नहीं आए। ये किसान क्या मांग रहे हैं? ये केवल यह कह रहे हैं कि जो सरकार ने दिया है, उसको हम लौटाना चाहते हैं। जिस हाल में हम थे, जो हमारे पास बचा था, उसको इन तीन कानूनों के माध्यम से मत छीनिए। ये किसान केवल यह गुहार करने आए हैं। आखिर किसान आपसे क्या मांग रहे हैं? MSP को बचाने की और उसको मजबूत करने की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। वही MSP, जिसकी मांग सबसे पहले मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी ने 1948 में संविधान सभा में की थी। यदि आप किसानों को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें उनकी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़ेगा। उस एमएसपी को मजबूत करने और उस एमएसपी को बचाने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है। उस APMC और उस मंडी व्यवस्था को बचाने के लिए किसान लड़ रहा है। जब चौधरी छोटू राम जी थे, 1938 में ज्वाइंट पंजाब था, पेशावर से पंजाब तक, पेशावर से पलवल तक जब एक राज्य था, उस समय मंडी व्यवस्था बनी थी। आज उस मंडी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है। उस उपभोक्ता को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है। Essential Commodities Act से जो असीमित भंडारण **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : माननीय दीपेन्द्र जी conclude कीजिए। आपका समय पूरा हो गया है।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Sir, I am concluding.

श्री उपसभापति : ऑलरेडी समय अधिक हो गया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : उस उपभोक्ता को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है। असीमित भंडारण, जमाखोरी की छूट के बाद किसान कह रहा है कि आप मुझसे सस्ते में खरीद कर उसका भंडारण करेंगे और उपभोक्ता को बहुत महंगे में बेचेंगे, तो जो मुनाफाखोरी होगी, उससे उपभोक्ता को भी बचाना है। उस उपभोक्ता के लिए भी किसान लड़ाई लड़ रहा है। आज किसान इनके साथ-साथ अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान की भी लड़ाई लड़ रहा है। मैं सदन के माध्यम से, इस सरकार से एक किसान का बेटे होने के नाते हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि स्थिति की गंभीरता को समझें। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता है, अपनी प्रजा की बात मानने से किसी सरकार की हार नहीं होती है। आप किसान की बात समझें। सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। किसान के ऊपर जो झूठे मुकदमे बने, उन मुकदमों को सरकार वापस ले और बड़ा दिल दिखाए। मैं अभी conclude करता हूं। सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, ताकि देशभक्त किसान के दिल में कोई अविश्वास पैदा न हो, कोई अविश्वास पैदा होने की गुंजाइश न हो। मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने के रंग दिए गए। मैं एक उदाहरण देकर **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude ... Please conclude. ऑलरेडी काफी समय हो चुका है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज दैनिक भास्कर अखबार में एक बात छपी थी। यहां पर बीजेपी की तरफ से मुझसे पूछा गया कि अभी कौन बैठे हैं? अखबार में छपा है, "बरोदा के 78 साल के पति का हाल जानने आंदोलन में पहुंची रामरति, 54 दिन के बाद पति को देखकर छलके आंसू, बोली - बालकां के बाबू तू ठीक सै।" मैं सरकार से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि वह किसानों की बात माने और आत्ममंथन भी करे। यह समय सरकार के आत्ममंथन का भी है। आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि किसान के लिए क्या किया। यह वही किसान है - आज़ादी के समय 30 करोड़ लोगों का पेट पालने के लिए आपको बाहर से अनाज लाना पड़ता था और आज 135 करोड़ लोगों का पेट पालने का काम...

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपसभापति जी, यह मेरा आखिरी वाक्य है। 135 करोड़ लोगों का पेट पालने का काम ये किसान करते हैं और फिर भी एक्सपोर्ट की गुंजाइश रखते हैं। आत्मनिर्भर इन्होंने बनाया है। आप आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। मैं आपको चेतावनी देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। भूपेन्द्र जी, आप तो हिंदी के ज्ञाता हैं, आत्ममुग्ध सरकारें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकती हैं - मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपसभापति महोदय, मैं एक वाक्य से साथ अपनी बात खत्म करता हूं - जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, दीपेन्द्र जी। ऑनरेबल श्री बिनोय विस्वम जी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Binoy Viswam.

SHRI BINOY VISWAM(Kerala): I will speak tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak.

SHRI BINOY VISWAM: No, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak. You have five minutes to speak today and then tomorrow.

SHRI BINOY VISWAM: Then it is okay.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I am sorry to say that I can only oppose this Motion because the Speech of the President runs against the national sentiments and the truth of the country. Ample times, the President mentioned about the farmers; twenty-seven times 'farmers' were mentioned in the Address, and often the Government speaks aloud *'Jai Jawan Jai Kisan'*. Sir, now the country has come to add one more to that *'Jai Jawan Jai Kisan*, and the Government adds 'Jai Adani, Jai Ambani, Jai FDI and Jai Corporates'. That is the script of this Address. Sir, how can a country support such an Address when the real people who freed this country are on a struggle path since months in the bitter cold of Delhi?

Sir, the hon. Prime Minister used to say about '*Mann Ki Baat*'. I request the PM to go and listen to the '*Mann Ki Baat*' in Singhu Border, in Tikri Border, in Kashipur and in Shahjahanpur. There is the real '*Mann Ki Baat*', not in the power corridors. This Address completely ignores them, neglects them and, at somplaces, the Address even insulted them. Sir, the truths are not mentioned in this Address. Sir, in the borders of Delhi, we can see that the Government has opened a warfront, a warfront with concrete barricades, with iron fences, with thorns and water cannons. For what? To suppress the movement of the '*Annadatas*'. You call them in loud words as '*Annadatas*'. But to make them retreat from the struggle, you use all kinds of forces. Sir, the truth is that the Government is not concerned even a bit about the real people who are India's '*Annadatas*', and the country now understands it. Sir, I have been there so many times, to all the borders, not as a leader, not as an M.P. but as an Indian, I went there to express my solidarity with them. What I could see there is simply a 'warfront'. One may go there and see as if it is a border with Pakistan or even China because the paramilitary forces and the Government forces are armed and they are ready. For whom? To treat them like enemies! Sir, it is high time for the Government to tell this country that all the *kisans* are the country's enemies. If they are not, the Government should listen to them; and if they are not the country's enemies, the Government should retreat from the present move and repeal the black laws. This is one thing.

2.00 P.M.

Sir, the fact is that -- so many facts are hidden in the Address and so I repeat -- the fact is that 86 per cent of the farmers in India have less than five acres of land.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Binoy Viswam, you may use the rest of your time tomorrow. Now, Special Mentions. Members may lay their Special Mentions on the Table. Shri Tiruchi Siva; please read the title and lay it on the Table.